

दैनिक

गाजियाबाद से प्रकाशित हिन्दी दैनिक

वेलाकम

इंडिया

RNI NO. UPHIN/2018/76874

नये भारत की नई सोच

वर्ष: 07 अंक: 172

बुधवार, 01 जुलाई-2026 (गाजियाबाद)

पेज-8

मूल्य-एक रुपया

E20 पेट्रोल पर सुप्रीम कोर्ट में बोली सरकार

पेट्रोल में इथेनॉल की मिलावट एक प्रयोग

वेलाकम इंडिया, नेटवर्क

नई दिल्ली। सरकार ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि पेट्रोल में 20 प्रतिशत इथेनॉल मिलाने का प्रोग्राम अभी भी एक चल रहा प्रयोग है और इस पॉलिसी का असर अगले साल तक और साफ हो जाएगा। यह बात इस प्रोग्राम को लेकर चल रही व्यापक बहस और चिंताओं के बीच कही गई है; कई लोगों को चिंता है कि इथेनॉल की ज्यादा मात्रा मिलाने से पुरानी गाड़ियां खराब हो सकती हैं और साथ ही फ्यूल की क्षमता भी कम हो सकती है। इस बीच, सरकार ने इन आशंकाओं को दूर करने की कोशिश करते हुए कहा है कि E20 पेट्रोल से गाड़ियों के मैकेनिकल पार्ट्स को नुकसान पहुंचने का कोई ठोस सबूत नहीं है और यह पॉलिसी भारत की एनर्जी सिक्योरिटी, किसानों और पर्यावरण के लिए फायदेमंद होगी। इस मामले पर आज



अर्दानीं जनरल आर वेंकटरमणी ने अपनी बात रखी। वे सरकारी कंपनी भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL) की एक याचिका पर बहस कर रहे थे, जिसमें 2025-26 सालाई ईंधन के लिए इथेनॉल आवंटन से जुड़े कर्नाटक हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी। 23 जून के अपने आदेश में हाई कोर्ट ने ऑयल मार्केटिंग कंपनियों (OMCs) BPCL, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन

लिमिटेड (HPCL) और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (IOC) को निर्देश दिया कि वे टैंटर को अंतिम रूप देने से पहले, इथेनॉल आवंटन बढ़ाने की मांग करने वाली एक डिस्ट्रिब्यूटर की अजीब विचार करें और उस पर फैसला लें। हालांकि, BPCL ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी कि हाई कोर्ट के आदेश से पेट्रोल में 20 प्रतिशत इथेनॉल मिलाने के सरकार के व्यापक नीतिगत लक्ष्य पर असर पड़ सकता है। अर्दानीं

जनरल ने कोर्ट को बताया, सरकार 20 प्रतिशत इथेनॉल मिलाने की प्रक्रिया पर प्रयोग कर रही है। अगले साल तक हमारे पास इसके नतीजे आ जाएंगे। सुनवाई के दौरान, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि BPCL ने इस आदेश के खिलाफ कर्नाटक हाई कोर्ट की डिवाइजन बेंच में अपील क्यों नहीं की। कोर्ट के सवाल का जवाब देते हुए अर्दानीं जनरल ने कहा कि इथेनॉल सप्लाई के कॉन्ट्रैक्ट पहले ही अक्टूबर 2025 के लिए तय

हो चुके हैं और इसी तरह की याचिकाएं कई हाई कोर्ट में पेंडिंग हैं। उन्होंने कहा कि इसका असर नेशनल पॉलिसी पर पड़ेगा। वेंकटरमणी ने ट्रांसफर याचिका दायर करने की इजाजत मांगी। उन्होंने तर्क दिया कि इस मामले पर अक्टूबर से पहले फैसला होना जरूरी है, क्योंकि तब इथेनॉल सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट के रिन्व्यूअल का समय आ जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर मैं पहले डिवाइजन बेंच और फिर दूसरे हाई कोर्ट में जाता हूँ, तो इसमें देरी होगी। सुनवाई के कुछ ही समय बाद, अर्दानीं जनरल ने इंडिया टुडे को साफ किया कि इथेनॉल की 20 प्रतिशत मिक्सिंग एक पॉलिसी से जुड़ा फैसला है, जिसके बदलने की संभावना नहीं है। उन्होंने आगे कहा मांग और दूसरी वजहों के आधार पर कंपनियों को मिलने वाले इथेनॉल की मात्रा कम या ज्यादा हो सकती है। भारत ने पेट्रोल में 20 प्रतिशत इथेनॉल मिलाने का अपना लक्ष्य पिछले साल ही हासिल

कर लिया, जो कि निर्धारित समय से पांच साल पहले था। तेल विपणन कंपनियों ने 1 अप्रैल से पूरे देश में इथेनॉल-मिश्रित पेट्रोल की आपूर्ति शुरू कर दी है। सरकार ने अब 2030 तक पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने की मात्रा को 30 प्रतिशत तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। आज की सुनवाई केंद्रीय तेल मंत्रालय के उस बयान के एक हफ्ते से भी कम समय बाद हुई, जिसमें मंत्रालय ने इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम को सुरक्षित, ग्राहकों के लिए फायदेमंद और आर्थिक रूप से लाभकारी बताया था। मंत्रालय ने उन चिंताओं को भी खारिज कर दिया था कि E20 फ्यूल के इस्तेमाल से गाड़ी के इंजियर्सस करेज पर असर पड़ सकता है। 24 जून को जारी एक बयान में मंत्रालय ने कहा कि E20 फ्यूल से इंजियर्सस पॉलिसी अमान्य हो सकती है, इस तरह के दावों की संबंधित पक्षों के साथ जांच की गई और वे गलत पाए गए।

राजनाथ सिंह का बड़ा बयान: मजबूत अर्थव्यवस्था, तकनीक और सुरक्षा से बनेगा विकसित भारत

वेलाकम इंडिया, नेटवर्क

नई दिल्ली। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को कहा कि 'वाइब्रेंट गुजरात' प्लेटफॉर्म एक देशव्यापी आंदोलन बन गया है जो विकसित भारत के विजन में योगदान दे रहा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि मजबूत अर्थव्यवस्था, तकनीकी क्षमता और राष्ट्रीय सुरक्षा मिलकर एक मजबूत राष्ट्र की नींव बनाते हैं। वडोदरा में 'वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस' के समापन सत्र को संबोधित करते हुए सिंह ने कहा कि यह पहल नए विचारों और अवसरों के जरिए गुजरात को आगे बढ़ाने में मदद कर रही है। उन्होंने कहा यह नए विचारों और नई संभावनाओं के जरिए गुजरात को आगे ले जाने की कोशिश है। मैंने यहाँ लगी प्रदर्शनी भी देखी। इसमें इंडस्ट्री, टरटए, आदिवासी उत्पादों और भारी उद्योगों सहित कई क्षेत्रों की भागीदारी है। रक्षा उद्योग में हो रहा काम भी तारीफ के काबिल है। आप हमें प्राइवेट इंडस्ट्री के लिए अनुकूल माहौल बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। देश के लिए गुजरात के योगदान की तारीफ करते हुए सिंह ने कहा कि राज्य ने महात्मा गांधी, सरदार वल्लभभाई पटेल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे



कई महान नेता दिए हैं। उन्होंने कहा गुजरात ने देश को महात्मा गांधी और सरदार वल्लभभाई पटेल दिए, और इसी धरती ने भारत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी दिए। जब से वे प्रधानमंत्री बने हैं, वैश्विक मंच पर भारत का सम्मान बढ़ा है। आज जब भारत अंतरराष्ट्रीय मंचों पर बोलता है, तो दुनिया ध्यान से सुनती है। इसका श्रेय नरेंद्र मोदी को जाता है, जिनका जन्म एक गुजराती माँ की कोख से हुआ था। रक्षा मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री पहले शुरू की थीं, जो पिछले दो दशकों में एक बड़े आंदोलन में बदल गई है। उन्होंने कहा कि वाइब्रेंट गुजरात मंच गुजरात के लोगों और उद्योगों की जीवंतता को दर्शाता है। इसकी शुरुआत 2003 में तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी।

सुवेदु अधिकारी सरकार ने पश्चिम बंगाल में 65 मुस्लिम उपसमूहों को ओबीसी आरक्षण सूची से बाहर का रास्ता दिखाया

वेलाकम इंडिया, नेटवर्क

नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल विधानसभा ने सोमवार को अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण व्यवस्था से जुड़े दो महत्वपूर्ण संशोधन विधेयकों को पारित कर राज्य की आरक्षण नीति में बड़ा बदलाव कर दिया। इन संशोधनों के तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति श्रेणी से बाहर की 66 समुदायों को अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण का लाभ देने का प्रावधान किया गया है। इनमें 54 हिंदू और 12 मुस्लिम समुदाय शामिल हैं। राज्य सरकार का दावा है कि यह कदम आरक्षण व्यवस्था को कानूनी रूप से मजबूत और अधिक पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है। विधानसभा में पारित किए गए दोनों विधेयकों में पश्चिम बंगाल पिछड़ा वर्ग आयोग को फिर से अधिक अधिकार दिए गए हैं। साथ ही तुणमूल कांग्रेस सरकार के समय तैयार की गई अन्य पिछड़ा वर्ग समुदायों की सूची को कानूनी मान्यता देने वाले प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है। राज्य के पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री गौरिशंकर घोष ने पश्चिम बंगाल पिछड़ा वर्ग संशोधन विधेयक 2026 तथा पश्चिम बंगाल पिछड़ा वर्ग आयोग संशोधन विधेयक 2026 को सदन में पेश किया। बहस और मत विभाजन के बाद दोनों विधेयक पारित हो गए। इन संशोधनों के माध्यम से वर्ष



2012 में तुणमूल कांग्रेस सरकार द्वारा किए गए बदलावों को वापस लेने की कोशिश की गई है। भारतीय जनता पार्टी लगातार आरोप लगाती रही है कि पिछली सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण का लाभ मुस्लिम समुदायों को अर्द्धतुलित तरीके से दिया, जबकि कई सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हिंदू समुदायों को अनदेखी की गई। नई व्यवस्था में मुस्लिम समुदायों की संख्या को काफी घटाया गया है। पहले की तुणमूल सरकार द्वारा तय ढांचे में 65 मुस्लिम उपसमूह शामिल थे, जबकि अब केवल 12 मुस्लिम समुदाय ही सूची में रखे गए हैं। इसी तरह हिंदू उपसमूहों की संख्या में भी बदलाव किया गया है। दरअसल, तुणमूल सरकार ने पहले अन्य पिछड़ा वर्ग सूची को बढ़ाकर 113 उपसमूह कर दिया था, जिनमें 77 मुस्लिम और 36 हिंदू समुदाय शामिल थे। बाद में इसे बढ़ाकर 140 उपसमूह कर दिया गया, जिनमें 77 मुस्लिम और 63 हिंदू समुदाय शामिल थे। इस

व्यवस्था को कलकत्ता उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी। वर्ष 2025 में उच्च न्यायालय ने इस सूची को रद्द कर दिया और कहा कि समुदायों को अन्य पिछड़ा वर्ग सूची में शामिल करने की प्रक्रिया कानूनी रूप से टिकाऊ नहीं थी। अदालत ने यह भी कहा था कि राज्य सरकार ने आयोग की उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया। बाद में उच्चतम न्यायालय ने कुछ मामलों में रोक हटाई, लेकिन अब नई सरकार ने व्यवस्था को फिर से पुराने 66 समुदायों वाले ढांचे पर ला दिया है। हम आपको याद दिला दें कि मई 2024 में कलकत्ता उच्च न्यायालय ने वर्ष 2010 के बाद जारी सभी अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाणपत्रों को रद्द कर दिया था। अदालत का मानना था कि समुदायों को सूची में शामिल करने की प्रक्रिया में गंभीर कानूनी कमियां थीं। इसके बाद इस साल मई में सत्ता में आई भारतीय जनता पार्टी सरकार ने अधिसूचना जारी कर अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण को पहले के 17 प्रतिशत से घटाकर 7 प्रतिशत कर दिया था। यह आरक्षण राज्य की 66 अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणियों तक सीमित कर दिया गया। नए संशोधनों के अनुसार राज्य सरकार पश्चिम बंगाल पिछड़ा वर्ग आयोग से परामर्श करके अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण का प्रतिशत तय करेगी और समय समय पर उसमें बदलाव भी कर सकेगी।

सचिन ने तेंदुलकर की तरह मास्टरस्ट्रोक खेला, एक्काथ शिंदे ने किया साफ-हम तोड़ते नहीं जोड़ते हैं

वेलाकम इंडिया, नेटवर्क

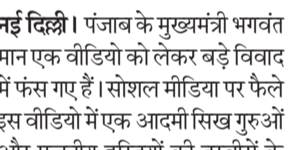


नई दिल्ली। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एक्काथ शिंदे ने मंगलवार को उद्भव गुट पर निशाना साधा। यह तब हुआ जब सोनियर टछड सचिन अहीर उनकी शिवसेना में शामिल हो गए और महायुति गठबंधन की ओर से महाराष्ट्र विधान परिषद के डिप्टी चेयरमैन पद के लिए नॉमिनेशन दाखिल किया। अहीर का पार्टी में स्वागत करते हुए शिंदे ने उनके इस राजनीतिक कदम की तुलना क्रिकेट के मैदान पर खेले गए 'मास्टरस्ट्रोक' से की। शिंदे ने कहा कि आज सचिन अहीर ने बिल्कुल सचिन तेंदुलकर की तरह शॉट खेला है। वह एक अहम नेता हैं। आज उन्होंने डिप्टी चेयरमैन पद के लिए नामांकन पत्र और महायुति का फॉर्म, दोनों भरे हैं। शिंदे ने उन आरोपों को खारिज कर दिया कि उनकी पार्टी दल-बदल के सहारे टिकी है। इसके बजाय, उन्होंने शिवसेना को एक बढ़ती हुई राजनीतिक ताकत के तौर पर पेश

किया। उन्होंने कहा कि हम लोगों को तोड़ते नहीं, बल्कि उन्हें साथ लाते हैं। अपने खेमे में लगातार शामिल हो रहे नेताओं का जिक्र करते हुए शिंदे ने कहा कि इस बदलाव के कारण साफ हैं। उन्होंने कहा, हल्लोग शिवसेना में क्यों आ रहे हैं? उन्होंने खुद ही इस सवाल का जवाब दिया है। शिंदे ने इस मौके पर 2022 की घटनाओं को भी याद किया और बताया कि 30 जून को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के तौर पर उनके शपथ लेने की सालगिरह है। उन्होंने कहा कि 2022 में लिए गए फैंसले से एक स्थिर सरकार बनी, जिसने महाराष्ट्र के विकास को तेजी देने के लिए केंद्र के साथ मिलकर काम किया है। उन्होंने कहा कि केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन से, केंद्र और राज्य मिलकर 'डबल-इंजन' सरकार चला रहे हैं। शिंदे ने आगे आरोप लगाया कि महायुति सरकार 2019 के विधानसभा चुनावों के बाद ही बन जानी चाहिए थी।

भगवंत मान के वायरल वीडियो पर महाविवाद, अकाल तख्त के फैसले के खिलाफ हुई पंजाब सरकार

वेलाकम इंडिया, नेटवर्क



नई दिल्ली। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान एक वीडियो को लेकर बड़े विवाद में फंस गए हैं। सोशल मीडिया पर फैले इस वीडियो में एक आदमी सिख गुरुओं और पुजनीय हरितियों की तस्वीरों के सामने हाथ में शराब का गिलास लिए दिख रहा है। लोगों का आरोप है कि शराब के छिंटे इन पवित्र तस्वीरों पर भी पड़े। इस बात से सिख संगठन और विरोधी पार्टियां बहुत नाराज हैं। उनका कहना है कि यह सिख गुरुओं का बड़ा अपमान है, क्योंकि सिख धर्म में पवित्र जगहों या धार्मिक तस्वीरों के पास शराब रखना बिल्कुल गलत माना जाता है।



अकाल तख्त का बड़ा फैसला
यह मामला सिख समुदाय की सबसे बड़ी धार्मिक संस्था 'अकाल तख्त' के पास पहुंचा। वहां पांच सदस्यों की कमेटी ने इस मामले की जांच की। सबसे बड़ा फैसला यह था कि क्या यह वीडियो नकली था। जिन लैब के नाम पर वे रिपोर्ट बनी थीं, उनका कोई अता-पता ही नहीं था।
पुलिस की कार्रवाई और नए दावे
इस मामले में गुरुग्राम पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है और नकली

रिपोर्ट बनाने के आरोप में कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया है। शक है कि इसमें पंजाब पुलिस के कुछ लोग भी शामिल हो सकते हैं। इस बीच मुख्यमंत्री भगवंत मान के बयान भी बदलते रहे। पहले उन्होंने इसे अकसे बना वीडियो बताया था, जो बाद में कहा कि वीडियो में दिख रहा आदमी कोई और है, जिसने उनके जैसा दिखने वाला मुखौटा पहन रखा था। अब सरकार पर जनता और धार्मिक संस्थाओं को धोखा देने के आरोप लग रहे हैं। यह विवाद इसलिए भी बहुत बड़ा हो गया है क्योंकि पंजाब सरकार ने हाल ही में धार्मिक अपमान को रोकने के लिए एक बहुत सख्त कानून पास किया है। पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने इस नए कानून को मंजूरी दे दी है। इसके तहत गुरु ग्रंथ साहिब का अपमान करने या इसकी साजिश रचने पर 10 साल से लेकर उम्रकैद तक की सजा और 25 लाख रुपये तक के जुर्माने का नियम है। अब विरोधी दल यह सवाल उठा रहे हैं कि जब सरकार ने इतना सख्त कानून बनाया है, तो क्या मुख्यमंत्री पर आरोप साबित होने पर उनके खिलाफ भी यही कार्रवाई होगी? कानूनी तौर पर यह मामला थोड़ा उलझा हुआ है, क्योंकि यह नया कानून मुख्य रूप से गुरु ग्रंथ साहिब के अपमान पर लागू होता है, तस्वीरों के अपमान पर नहीं।

तेज आंधी से ई-रिक्शा पर गिरा विशाल नीम का पेड़, 5 यात्रियों की दर्दनाक मौत, 3 गंभीर घायल



वेलाकम इंडिया, नेटवर्क

नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले से एक बेहद दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई है। फरिहा क्षेत्र में सोमवार रात आई अचानक तेज आंधी के कारण एक विशाल नीम का पेड़ चलती ई-रिक्शा पर गिर गया। इस भीषण हादसे में ई-रिक्शा पर सवार पांच यात्रियों की मौत पर ही मौत हो गई, जबकि तीन अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और प्रशासनिक

अधिकारी मौके पर पहुंचे और तत्काल राहत कार्य शुरू किया। जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा ने बताया कि फरिहा थानाक्षेत्र में चिड़रई गांव के पास रात करीब साढ़े आठ बजे एक ई-रिक्शा अवागढ़ से आ रहा था, तभी पृथ्वीपुर-चिड़रई मार्ग पर अचानक आयी तेज आंधी से नीम का एक बड़ा पेड़ अचानक उस पर गिर गया। उन्होंने बताया कि इस हादसे में ई-रिक्शा सवार सभी आठ लोग पेड़ के नीचे दब गए, जिन्हें पुलिस ने पेड़ हटवाकर बाहर निकाला और ट्रामा सेंटर भेजा।

जनरल उपेन्द्र द्विवेदी ने जनरल धीरज सेठ को सौंपी भारतीय सेना की कमान, जाते जाते कह गये बहुत बड़ी बात

वेलाकम इंडिया, नेटवर्क

नई दिल्ली। भारतीय सेना के प्रमुख जनरल उपेन्द्र द्विवेदी ने चार दशक से अधिक लंबे सैन्य जीवन के बाद सेना प्रमुख का पदभार जनरल धीरज सेठ को सौंप दिया। इस अवसर पर आयोजित विदाई समारोह में जनरल द्विवेदी ने भारतीय सेना में सेवा को अपने जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य बताया। उन्होंने सैनिकों, पूर्व सैनिकों, उनके परिवारों तथा देशवासियों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि भारतीय सेना की वास्तविक शक्ति किसी एक व्यक्ति से नहीं, बल्कि जवानों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों और देश के नागरिकों के अटूट विश्वास से आती है। पदभार छोड़ने से पहले जनरल उपेन्द्र द्विवेदी ने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पहुंचकर शहीद सैनिकों

को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि सैनिक स्कूल से शुरू हुई उनकी यात्रा अविस्मरणीय रही है और चार दशकों से अधिक समय तक भारतीय सेना में सेवा देना उनके लिए गर्व और संतोष का विषय है। उन्होंने उन सभी सैनिकों को नमन किया जिन्होंने कर्तव्य निभाते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया। अपने संबोधन में जनरल द्विवेदी ने पिछले दो वर्षों के दौरान भारतीय सेना की तैयारियों और सतर्कता का विशेष उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि उत्तरी सीमाओं पर चलाए गए अभियान 'प्लो लेपर्ड' के तहत सेना ने पूरी मजबूती और सतर्कता के साथ अपनी जिम्मेदारियां निभाईं। वहीं पश्चिमी मोर्चे पर भी सेना ने गंभीरता और संयम के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया, जिसका उदाहरण 'ऑपरेशन सिंदूर' है।



उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े सभी मामलों में भारतीय सेना ने स्पष्ट उद्देश्य, अनुशासन और जिम्मेदारी की भावना के साथ अपने दायित्व पूरे किए हैं। जनरल द्विवेदी ने तीनों सेनाओं के बीच बढ़ते तालमेल को देश की सुरक्षा व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि सेना, नौसेना और वायुसेना ने साझा दृष्टि, आपसी विश्वास

और बेहतर समन्वय के साथ कार्य किया है। उन्होंने कहा कि भविष्य का युद्ध अधिक संयुक्त, समन्वित और क्षेत्र आधारित होगा, इसलिए तीनों सेनाओं को साथ मिलकर देखने, निर्णय लेने और कार्रवाई करने की दिशा में आगे बढ़ना होगा। उन्होंने कहा कि यही सोच देश की राष्ट्रीय सुरक्षा के नए स्वरूप को मजबूत कर रही है। सेना प्रमुख के रूप में अपने कार्यकाल को समाप्त

करते हुए जनरल उपेन्द्र द्विवेदी ने अपने उत्तराधिकारी जनरल धीरज सेठ पर पूरा भरोसा जताया। उन्होंने कहा कि जनरल धीरज सेठ एक अनुभवी सैनिक और सक्षम नेता हैं। इस सिलेब में भारतीय सेना नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेगी। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि भारतीय सेना अपनी गौरवशाली परंपराओं, पेशेवर क्षमता और संकल्प को बनाए रखे हुए भविष्य की हर चुनौती का सामना करने के लिए सदैव तैयार रहेगी। हम आपको बता दें कि विदाई समारोह भावुक और गौरवपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ, जहां जनरल उपेन्द्र द्विवेदी ने भारतीय सेना के भविष्य को सुरक्षित और मजबूत हाथों में बताते हुए अपनी जिम्मेदारी औपचारिक रूप से जनरल धीरज सेठ को सौंप दी। हम आपको यह भी बता दें कि पदभार

छोड़ने से पहले दिये विभिन्न साक्षात्कारों में जनरल उपेन्द्र द्विवेदी ने वास्तविक नियंत्रण रेखा की स्थिति को स्थिर लेकिन संवेदनशील बताया। उन्होंने कहा कि भारत और चीन के बीच हाल के समझौतों से सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थिरता बड़ी है और दोनों पक्ष एक दूसरे की चिंताओं के प्रति अधिक संवेदनशीलता दिखा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सैन्य स्तर की वाताओं, हाटलाइन, पतंग बैठक और कमांडर स्तर की बातचीत के माध्यम से सीमाई मुद्दों को संभालने में मदद मिली है। उन्होंने बताया कि भारतीय सेना की प्राथमिकता सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखने, संवाद के माध्यम से स्थानीय समस्याओं का समाधान करने तथा किसी भी स्थिति से निपटने के लिए एकीकृत सैन्य तैयारी बनाए रखने की है।

संपादक की कलम से

संतुलित कूटनीति से उभरता भारत का वैश्विक नेतृत्व

भारत की विदेश नीति की सबसे बड़ी विशेषता उसकी संतुलित, स्वतंत्र और दूरदर्शी सोच रही है। विश्व राजनीति के बदलते परिदृश्य, महाशक्तियों के बीच बढ़ती प्रतिस्पर्धा, क्षेत्रीय संघर्षों और वैश्विक अस्थिरताओं के दौर में भारत ने जिस परिपक्वता और विवेक का परिचय दिया है, उसने उसे विश्व मंच पर एक विश्वसनीय, जिम्मेदार और प्रभावशाली राष्ट्र के रूप में स्थापित किया है।



ललित शर्मा संपादक

इरान के पूर्व सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई के निधन के उपरांत उनके अंतिम संस्कार में भारत की ओर से उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल को भेजने का निर्णय भी इसी संतुलित और व्यावहारिक विदेश नीति का परिचायक है। यह केवल एक राजनयिक औपचारिकता नहीं, बल्कि भारत और इरान के बीच सदियों पुराने सांस्कृतिक, सभ्यतागत एवं रणनीतिक संबंधों के प्रति सम्मान और प्रतिबद्धता का प्रतीक है। भारत की ओर से विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मर्गेरिटा तथा बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) सैयद अता हसन के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल का तेहरान जाना यह स्पष्ट करता है कि भारत अपने मित्र देशों के साथ संबंधों को केवल सामरिक दृष्टि से नहीं, बल्कि मानवीय संबेदनाओं के आधार पर भी देखता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं इस अवसर पर उपस्थित नहीं हो सके, क्योंकि उनके पूर्व निर्धारित कार्यक्रम थे, किंतु भारत की गरिमापूर्ण उपस्थिति ने यह संदेश अत्यंत दृढ़ता से दिया कि भारत अपने मित्र देशों के साथ-सुख-दुःख में सहभागी बनने की परंपरा का निर्वाह करता है।

वस्तुतः भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती विभिन्न वैश्विक शक्तियों के बीच संतुलन बनाए रखने की रही है। आज भारत के अमेरिका, रूस, इजरायल, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, यूरोप, जापान और आसियान देशों के साथ मजबूत रणनीतिक एवं आर्थिक संबंध हैं। दूसरी ओर इरान के साथ भी उसके ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और ऊर्जा संबंध अत्यंत महत्वपूर्ण रहे हैं। ऐसे में किसी एक पक्ष के साथ अत्यधिक निकटता दूसरे पक्ष के साथ संबंधों को प्रभावित कर सकती है। किंतु भारत ने संदेह यह सिद्ध किया है कि वह अपने राष्ट्रीय हितों के अनुरूप स्वतंत्र विदेश नीति का अनुसरण करता है। इरान से जुड़े हालिया घटनाक्रमों पर भारत की प्रतिक्रिया भी अत्यंत संतुलित रही। भारत ने इरानी दूतावास जाकर शोक संवेदना व्यक्त की, किंतु किसी प्रकार के अंतरराष्ट्रीय आरोप-प्रत्यारोप में स्वयं को शामिल नहीं किया। भारत ने न तो अमेरिका की आलोचना की और न ही इजरायल के विरुद्ध कोई आक्रामक टिप्पणी की। यह वही कूटनीतिक परिपक्वता है, जिसने भारत को वैश्विक राजनीति में एक जिम्मेदार शक्ति के रूप में स्थापित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की विदेश नीति का मूल आधार 'राष्ट्रहित सर्वोपरि' रहा है। इसी कारण भारत ने किसी भी अंतरराष्ट्रीय दबाव के बजाय अपने राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता दी है। रूस-यूक्रेन युद्ध इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। पश्चिमी देशों के दबाव के बावजूद भारत ने रूस से तेल खरीदना जारी रखा, क्योंकि वह देश की ऊर्जा सुरक्षा के लिए आवश्यक था। साथ ही भारत ने अमेरिका और यूरोपीय देशों के साथ अपने संबंधों को भी मजबूत बनाए रखा। यह संतुलन साधना आसान नहीं था, किंतु भारत ने इसे सफलतापूर्वक निभाया। यही कारण है कि आज भारत को किसी गुट विशेष का सदस्य नहीं, बल्कि एक स्वतंत्र वैश्विक शक्ति के रूप में देखा जाता है। भारत और इरान के संबंध हजारों वर्षों पुराने हैं।



डॉ. सत्यवान सौरव लेखक

हरियाणा में सामने आए 661 करोड़ रुपये के कथित आईडीएफसी बैंक प्रकरण ने केवल एक वित्तीय अनियमितता के आरोपों को जन्म नहीं दिया है, बल्कि प्रशासनिक जवाबदेही, वित्तीय अनुशासन, संस्थागत पारदर्शिता और शासन व्यवस्था की विश्वसनीयता पर भी गंभीर बहस छेड़ दी है। समाचारों के अनुसार इस मामले में वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों के नाम सामने आए हैं, जांच एजेंसियाँ सक्रिय हैं, कुछ गिरफ्तारियाँ हुई हैं, कुछ अधिकारियों को निलंबित किया गया है तथा कुछ ने न्यायालय में अग्रिम जमानत याचिकाएँ दायर की हैं। ऐसे में यह प्रकरण केवल किसी बैंक, किसी विभाग या किसी अधिकारी तक सीमित नहीं रह जाता, बल्कि यह पूरे प्रशासनिक ढाँचे की कार्यप्रणाली पर प्रश्नचिह्न खड़ा करता है।

सबसे पहले यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध लगाए गए आरोप तब तक केवल आरोप ही माने जाते हैं, जब तक सक्षम न्यायालय उन्हें प्रमाणित न कर दे। भारतीय संविधान प्रत्येक नागरिक को निष्पक्ष सुनवाई और न्यायिक प्रक्रिया का अधिकार देता है। इसलिए किसी भी आरोपी को दोषी मान लेना न्याय के सिद्धांतों के विपरीत होगा। दूसरी ओर, यदि सार्वजनिक धन से जुड़ी इतनी बड़ी राशि के संबंध में गंभीर आरोप सामने आते हैं, तो उनकी निष्पक्ष, पारदर्शी और

समयबद्ध जांच भी उतनी ही आवश्यक है। लोकतंत्र में न्याय केवल होना ही नहीं चाहिए, बल्कि होता हुआ दिखाई भी देना चाहिए। यह कथित घोटाला इसलिए अधिक गंभीर माना जा रहा है क्योंकि इसमें सरकारी धन के प्रबंधन पर प्रश्न उठे हैं। सरकारी धन वास्तव में जनता का धन होता है। यह वह राशि है जो नागरिक करों के माध्यम से सरकार को देते हैं ताकि उसका उपयोग शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण, ग्रामीण विकास, सिंचाई, सड़क, रोजगार और अन्य जनकल्याणकारी योजनाओं पर किया जा सके। यदि ऐसे धन के उपयोग या संरक्षण में किसी प्रकार की अनियमितता की आशंका उत्पन्न होती है, तो उसका प्रभाव केवल सरकारी खातों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि शासन के प्रति जनता के विश्वास पर भी पड़ता है। समाचारों के अनुसार इस मामले में सरकारी विभागों के बैंक खाते, निजी बैंक में धन जमा कराने की प्रक्रिया, प्रशासनिक स्वीकृतियाँ और वरिष्ठ अधिकारियों की भूमिका जैसे अनेक प्रश्न जांच के दायरे में हैं। यदि जांच में यह सिद्ध होता है कि नियमों की अनदेखी हुई, तो जिम्मेदारी तब होना स्वाभाविक होगा। यदि आरोप असत्य सिद्ध होते हैं, तब भी यह जानना आवश्यक होगा कि ऐसी परिस्थितियाँ क्यों बनीं जिनसे इतने बड़े स्तर पर संदेह उत्पन्न हुआ। दोनों ही स्थितियों में व्यवस्था की समीक्षा आवश्यक है। भारतीय प्रशासनिक सेवा देश की सर्वोच्च सिविल सेवाओं में मानी जाती है। आईएएस अधिकारी केवल शासन चलाने वाले अधिकारी नहीं होते, बल्कि वे संविधान के मूल्यों के संरक्षक भी माने जाते हैं। जनता उनकी निष्पक्षता, ईमानदारी और निष्पक्षता पर विश्वास करती है। इसलिए जब किसी वरिष्ठ अधिकारी का नाम किसी वित्तीय विवाद में सामने आता है, तो उसकी प्रतिध्वनि पूरे प्रशासनिक तंत्र में सुनाई देती है। ऐसे मामलों में पारदर्शिता इसलिए भी आवश्यक हो जाती है ताकि ईमानदार



अधिकारियों को प्रतिष्ठा सुरक्षित रहे और दोषी व्यक्ति कानून से बच न सके। यह मामला प्रशासनिक निर्णय प्रक्रिया पर भी गंभीर प्रश्न खड़े करता है। किसी सरकारी खाते को किसी विशेष बैंक में खोलने या बड़ी राशि जमा कराने का निर्णय क्या केवल एक अधिकारी का होता है? सामान्यतः ऐसे निर्णयों में अनेक स्तरों पर स्वीकृतियाँ, वित्तीय नियम, विभागीय प्रक्रियाएँ और लेखा प्रणाली शामिल होती हैं। यदि इन सभी स्तरों के बावजूद कोई कथित अनियमितता संभव हुई, तो इसका अर्थ है कि कहीं न कहीं संस्थागत नियंत्रण कमजोर रहा। इसलिए केवल व्यक्तियों की जिम्मेदारी तय करना पर्याप्त नहीं होगा; पूरी प्रणाली की समीक्षा आवश्यक होगी। आज भारत डिजिटल शासन की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली (ट्रेंज़र), ई-ऑफिस, डिजिटल भुगतान, ऑनलाइन लेखांकन और रिजल-टाइम मॉनिटरिंग जैसी व्यवस्थाओं का उद्देश्य ही यह है कि वित्तीय अनियमितताओं को संभावना न्यूनतम हो। यदि इतने बड़े स्तर पर कथित गड़बड़ी की आशंका सामने आती है, तो यह प्रश्न स्वाभाविक है कि क्या उपलब्ध तकनीकी प्रणालियों का सही उपयोग हुआ? क्या समय पर ऑडिट किया गया? क्या किसी ने असामान्य लेन-देन पर ध्यान नहीं दिया? क्या आंतरिक चेतावनी तंत्र प्रभावी नहीं था?

सरकारी विभागों में आंतरिक ऑडिट व्यवस्था का उद्देश्य केवल लेखा परीक्षण करना नहीं होता, बल्कि संभावित जोखिमों की समय रहते पहचान करना भी होता है। यदि करोड़ों रुपये का लेन-देन लंबे समय तक बिना किसी प्रभावी आपत्ति के चलता रहा, तो यह केवल व्यक्तिगत नहीं बल्कि संस्थागत विफलता भी मानी जाएगी। इसलिए इस प्रकरण से सीख लेकर ऑडिट व्यवस्था को अधिक सक्षम और तकनीकी आधारित बनाने की आवश्यकता है। लोकतंत्र में जांच एजेंसियों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। जब किसी बड़े मामले की जांच होती है, तब जनता केवल परिणाम नहीं देखती बल्कि पूरी प्रक्रिया पर भी नजर रखती है। जांच निष्पक्ष हो, तथ्यों पर आधारित हो और किसी राजनीतिक या प्रशासनिक दबाव से मुक्त दिखाई दे-यही उसकी सबसे बड़ी विश्वसनीयता है। यदि जांच एजेंसियों पर विश्वास कमजोर होता है, तो न्याय व्यवस्था की साख भी प्रभावित होती है। मीडिया की भूमिका भी ऐसे मामलों में अत्यंत संवेदनशील होती है। लोकतंत्र में मीडिया का दायित्व सूचना देना और प्रश्न पूछना है, लेकिन किसी भी व्यक्ति को न्यायालय से पहले दोषी घोषित करना उचित नहीं है। मीडिया ट्रायल कई बार न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित करता है और समाज में पूर्वाग्रह उत्पन्न करता है। इसलिए समाचारों की

प्रस्तुति तथ्यों और जिम्मेदारी के साथ होनी चाहिए। इस प्रकरण ने सरकारी बैंकिंग व्यवस्था पर भी प्रश्न उठाए हैं। क्या सरकारी विभागों के बैंक खातों के संचालन के लिए स्पष्ट राष्ट्रीय नीति है? किन परिस्थितियों में सरकारी राशि निजी बैंक में रखी जा सकती है? क्या इसके लिए विशेष अनुमति आवश्यक होती है? क्या संबंधित विभागों ने सभी वित्तीय नियमों का पालन किया? यदि किया, तो वे दस्तावेज सार्वजनिक जांच के लिए उपलब्ध होने चाहिए। यदि नहीं किया गया, तो जिम्मेदारी तब होना आवश्यक है। प्रशासनिक नैतिकता केवल कानून का पालन करने तक सीमित नहीं होती। नैतिक प्रशासन का अर्थ है कि प्रत्येक निर्णय में सार्वजनिक हित सर्वोपरि रहे। संविधान के प्रति निष्ठा, ईमानदारी, निष्पक्षता और जवाबदेही प्रशासनिक सेवा की आधारशिला हैं। यदि इन मूल्यों से समझौता होता है, तो केवल आर्थिक नुकसान नहीं होता, बल्कि लोकतांत्रिक संस्थाओं की विश्वसनीयता भी कमजोर होती है। इस मामले का एक सकारात्मक पक्ष भी है। यदि इसकी निष्पक्ष जांच होती है और उसके आधार पर संस्थागत सुधार किए जाते हैं, तो भविष्य में ऐसी घटनाओं की संभावना कम की जा सकती है। कई बार बड़े विवाद प्रशासनिक सुधारों का कारण भी बनते हैं। इसलिए आवश्यक है कि इस मामले को केवल कानूनी विवाद न मानकर एक सुधारात्मक अवसर के रूप में भी देखा जाए। सरकार को चाहिए कि वह सरकारी खातों के संचालन की नीति को और अधिक पारदर्शी बनाए। सभी बड़े वित्तीय लेन-देन की रूप में डिजिटल निगरानी हो-स्वतंत्र फॉरेंसिक ऑडिट की व्यवस्था हो। विभागीय अधिकारियों की जिम्मेदारियाँ स्पष्ट रूप से निर्धारित हों। यदि किसी स्तर पर नियमों का उल्लंघन होता है, तो समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। साथ ही ईमानदार अधिकारियों को अनापेक्षित उत्पीड़न से भी बचाया जाए। विसलक्लोअर संरक्षण प्रणाली

को भी मजबूत करना समय की आवश्यकता है। अनेक बार विभागों के भीतर कार्यरत कर्मचारी अनियमितताओं की जानकारी रखते हैं, लेकिन सुरक्षा के अभाव में सामने नहीं आते। यदि उन्हें कानूनी संरक्षण और गोपनीयता मिले, तो अनेक वित्तीय अनियमितताओं को प्रारंभिक स्तर पर ही रोका जा सकता है। भारत आज वैश्विक निवेश का प्रमुख केंद्र बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। ऐसे समय में प्रशासनिक पारदर्शिता और वित्तीय अनुशासन केवल आंतरिक आवश्यकता नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय विश्वसनीयता का भी प्रश्न है। निवेशक उन देशों पर अधिक विश्वास करते हैं जहाँ कानून का शासन मजबूत हो, सार्वजनिक धन सुरक्षित हो और संस्थाएँ उत्तरदायी हों। अंततः यह मामला केवल 661 करोड़ रुपये का नहीं है। यह उस विश्वास का प्रश्न है जो जनता शासन व्यवस्था पर करती है। यदि दोषी बच जाते हैं तो व्यवस्था पर प्रश्न उठते हैं, और यदि निर्दोषों को बिना पर्याप्त आधार के दोषी ठहराया जाता है तो न्याय व्यवस्था की विश्वसनीयता प्रभावित होती है। इसलिए इस पूरे प्रकरण में संतुलन, निष्पक्षता और संवैधानिक मर्यादा का पालन सबसे अधिक आवश्यक है। लोकतंत्र की असली शक्ति सत्ता नहीं, बल्कि जनता का विश्वास है। यह विश्वास पारदर्शिता, जवाबदेही और न्याय से ही अर्जित होता है। इसलिए आवश्यक है कि इस प्रकरण की जांच पूरी निष्पक्षता के साथ हो, दोषी चाहे किनका भी प्रभावशाली क्यों न हो, उसे कानून के अनुसार दंड मिले और यदि कोई निर्दोष है तो उसकी प्रतिष्ठा भी पूर्ण रूप से बहाल हो। यही शासन की पहचान है और यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी कसौटी भी। तभी 661 करोड़ रुपये का यह चर्चित प्रकरण केवल एक विवाद बनकर नहीं रहेगा, बल्कि प्रशासनिक सुधार और बेहतर शासन व्यवस्था की दिशा में एक महत्वपूर्ण सबक सिद्ध होगा।

विकास की आड़ में जमीन की लूट: भूमाफिया, सत्ता और कानून का गटजोड़



पंकज शर्मा लेखक

जब किसी राष्ट्र में विकास का अर्थ केवल कंक्रीट की ऊँची इमारतों, चौड़ी सड़कों, औद्योगिक गलियारों और चमकदार परियोजनाओं तक सीमित होने लगे, तब यह प्रश्न उठाना स्वाभाविक है कि उस विकास की वास्तविक कीमत कौन चुका रहा है। क्या विकास केवल आँकड़ों की वृद्धि का नाम है, या वह नागरिकों के अधिकारों, सम्मान, आजीविका और न्याय की भी रक्षा करता है? यही प्रश्न भूमि के मुद्दे को लोकतांत्रिक विमर्श के केंद्र में ला खड़ा करता है। भूमि किसी भी समाज के लिए केवल आर्थिक संसाधन नहीं होती। वह स्मृतियों, संस्कृतियों, परंपराओं, श्रम, आत्मसम्मान और पीढ़ियों के संघर्ष का आधार होती है। किसान के

लिए भूमि उसकी जीविका है, ग्रामीण परिवार के लिए उसका भविष्य, और समाज के लिए उसकी सामूहिक धरोहर। इसलिए जब विकास के नाम पर भूमि का उपयोग बदला जाता है, तो यह केवल प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं रहती; यह न्याय, सहभागिता और संवैधानिक मूल्यों की कसौटी बन जाती है। आर्थिक विकास और आधारभूत संरचना का विस्तार किसी भी आधुनिक राष्ट्र की आवश्यकता है। नई सड़कें, अस्पताल, विद्यालय, रेलमार्ग, उद्योग और ऊर्जा परियोजनाएँ जनकल्याण का माध्यम बन सकती हैं। लेकिन किसी भी परियोजना की सफलता केवल उसके आकार से नहीं, बल्कि उससे प्रभावित लोगों के साथ किए गए व्यवहार से भी मापी जानी चाहिए। यदि विकास की प्रक्रिया पारदर्शी, न्यायपूर्ण और सहभागितापूर्ण न हो, तो वह विश्वास के बजाय असंतोष को जन्म देती है। भूमि से जुड़े विवादों में सबसे बड़ी चुनौती यही है कि एक ओर सार्वजनिक हित की परियोजनाएँ होती हैं और दूसरी ओर नागरिकों के वैध अधिकार। इन दोनों के बीच संतुलन स्थापित करना लोकतांत्रिक शासन की जिम्मेदारी है। यह संतुलन तभी संभव है जब भूमि अभिलेख स्पष्ट हों, निर्णय-प्रक्रिया



पारदर्शी हो, प्रभावित लोगों से सार्थक संवाद किया जाए, उचित मुआवजा दिया जाए और पुनर्वास केवल औपचारिकता न होकर वास्तविक पुनर्स्थापन का माध्यम बने। समय-समय पर देश के विभिन्न हिस्सों से भूमि विवाद, अवैध कब्जे, फर्जी लेगो प्रभावशाली और साधारण व्यक्ति के लिए अलग-अलग मानदंड हैं, तो लोकतांत्रिक संस्थाओं में विश्वास कमजोर पड़ता है। इसलिए भूमि से जुड़े प्रत्येक निर्णय में पारदर्शिता, स्वतंत्र जांच, समयबद्ध न्याय और सार्वजनिक जवाबदेही अत्यंत आवश्यक हैं। विस्थापन का प्रश्न केवल मकान बदलने का प्रश्न नहीं है। यह सामाजिक संबंधों, शिक्षा,

स्वास्थ्य, आजीविका, सांस्कृतिक पहचान और मनोवैज्ञानिक सुरक्षा से जुड़ा विषय है। किसी परिवार को उसकी भूमि से हटाना तभी न्यायसंगत माना जा सकता है जब उसके भविष्य को पहले से अधिक सुरक्षित और सम्मानजनक बनाने की ठोस व्यवस्था की जाए। विकास यदि लोगों को असुरक्षामें छोड़ दे, तो उसकी नैतिक वैधता पर प्रश्न उठाना स्वाभाविक है। सतत विकास का अर्थ यही है कि आर्थिक प्रगति और सामाजिक न्याय साथ-साथ चलें। कृषि भूमि, जल स्रोतों, पर्यावरण और स्थानीय समुदायों पर पड़ने वाले प्रभावों का वैज्ञानिक मूल्यांकन किए बिना लिए गए निर्णय दीर्घकाल में गंभीर परिणाम उत्पन्न कर सकते हैं। विकास की वास्तविक सफलता तब है जब वह वर्तमान की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए भविष्य की पीढ़ियों के अधिकारों की भी रक्षा करे। लोकतंत्र में मीडिया, न्यायपालिका, नागरिक समाज और जागरूक नागरिकों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। स्वतंत्र पत्रकारिता का दायित्व है कि वह भूमि, पुनर्वास, प्रशासनिक प्रक्रियाओं और नीति-निर्माण से जुड़े प्रश्नों पर तथ्यपरक, संतुलित और निर्भय विमर्श प्रस्तुत करे। वहीं सार्वजनिक संस्थाओं का

दायित्व है कि वे आलोचना को लोकतांत्रिक उत्तरदायित्व के रूप में स्वीकार करें और पारदर्शिता को अपनी कार्यप्रणाली का मूल तत्व बनाएं। अंततः किसी राष्ट्र की महानता उसकी इमारतों की ऊँचाई से नहीं, बल्कि उसके न्याय की ऊँचाई से मापी जाती है। विकास तभी सार्थक है जब वह नागरिकों की अधिकारों से वंचित न करे, बल्कि उन्हें अधिक सुरक्षित, अधिक सम्मानजनक और अधिक समृद्ध जीवन प्रदान करे। भूमि पर अधिकारों और विकास के बीच संतुलन स्थापित करना केवल प्रशासनिक चुनौती नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक नैतिकता की परीक्षा है। आज आवश्यकता विकास और अधिकारों के बीच कुत्रिम संघर्ष खड़ा करने की नहीं, बल्कि ऐसी व्यवस्था पारदर्शिता, संवैधानिक मूल्यों, विधि के शासन और जनभागीदारी के साथ आगे बढ़े। जब कानून निष्पक्ष होगा, निर्णय पारदर्शी होंगे और नागरिकों का आवाज को समान महत्व मिलेगा, तभी विकास का मार्ग विश्वास का मार्ग बनेगा-और तभी राष्ट्र की प्रगति केवल आर्थिक उपलब्धि नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय की भी कहानी कहलाएगी।

चोर चोर मौसेरे भाई उदय किशोर साह कविता



चोर चोर मौसेरा भाई कहलाता बैरी को परास्त करने साथ निभाता अच्छे बुरे की खुद ना कोई है ज्ञान मंशा होता दुश्मन को करना परेशान दामदार चरित्र में छुपा है दिल काला सुनीति के घर पे जड़ दी है ये ताला कुविचार की करता ये मिल जयकार आपने मतलब का बन जाता ये यार गोल गोल सब्जबाग ये दिखलाता घुमा घुमा कर अपनी बात समझाता इनके अन्दर में छिपा है कोई काल कालनेमि बन कर आता ये कमाल छ्त्रा वंश का ये है बड़ा बहुरूपिया नकली चरित्र का होता ये भूतिया इनके अन्दर है भेड़िये जैसी चाल वाकपटु में ये होता डाली का बेटाल धर्मकर्म की नीति का ये है दुश्मन चेहरे पे लगाये है सेवा की चिलमन कुदरती होता है ये सब विकराल अच्यल दर्जे का ये है जालिम दलाल

स्वामी, मुद्रक एवं प्रकाशक ललित कुमार द्वारा वेलकम इंडिया प्रिन्टर्स, 1/26, साउथ साइड, जी टी रोड, गाजियाबाद-201001 से मुद्रित करारक ग्राउन्ड फ्लोर, दुर्गा टॉवर, आर.डी. सी राजनगर, गाजियाबाद 201002 से प्रकाशित किया। संपादक: ललित शर्मा सम्पर्क सूत्र: 9891116568

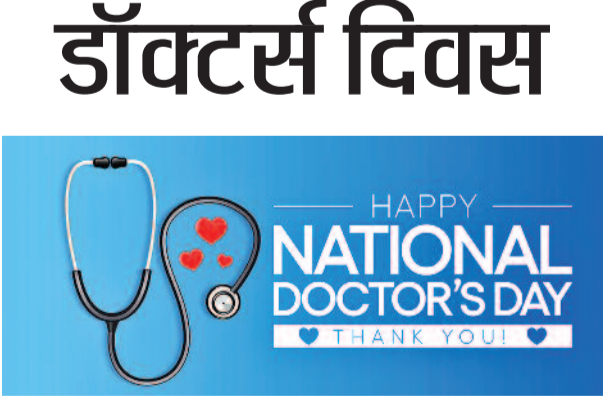
किसी कानूनी विवाद की स्थिति में निपटारा गाजियाबाद न्यायालय में ही होगा।



संत राजिन्दर सिंह लेखक

आज का दिन पूरे भारतवर्ष में डॉक्टर्स दिवस रूप में मनाया जा रहा है। डॉक्टर्स हमारे जीवन में प्रमुख भूमिका निभाते हैं ताकि समाज में रह रहे लोगों के स्वास्थ्य की देखभाल हो सके। अगर हम शारीरिक रूप से कभी बीमार होते हैं तो एकदम से हमारे दिमाग में डॉक्टर का ख्याल आता है क्योंकि हम यह अच्छी तरह जानते हैं कि वो ही हमें स्वस्थ कर सकते हैं। इसलिए डॉक्टरों को एक सम्मानीय पेशा है क्योंकि इसमें सेवा व त्याग की भावना होती है। आज पुरी दुनिया करीना को महामारी से जूझ रही है। दुनिया भर के हजारों डॉक्टर्स, नर्स,

अन्य स्वास्थ्य कर्मी और शोधकर्ता सभी अथक प्रयास कर रहे हैं जिससे कि लोगों के जीवन को बचाया जा सके। वे अनेक कठिनाईयों के बाद भी अपना कार्य बड़ी ईमानदारी और मेहनत से कर रहे हैं, जिससे कि लाखों लोगों को मदद मिल रही है। आईये! इस बात को समझने की कोशिश करें कि एक डॉक्टर बनने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। विद्यार्थियों को अनेक वर्ष मेडिकल कॉलेज में चिकित्सा विज्ञान से संबंधी कौर्स को करने के लिए लगाने पड़ते हैं। मानव शरीर के प्रत्येक अंग, हरेक औषधि या दवाई अथवा प्रत्येक बीमारी को याद रखने के लिए और रोगियों का सही हंम के ईलाज व उपचार करने के लिए, अनेक वर्षों तक कठोर अध्ययन की जरूरत होती है, जिसमें एक प्रबल लगन की आवश्यकता पड़ती है, जब तक कि उस क्षेत्र में निपुणता हासिल न कर ली जाए। उसके पश्चात व्यावहारिक प्रशिक्षण आदि में बहुत सा समय गुजारना पड़ता है। अगर हम डॉक्टर्स के जीवन को देखें तो वह निकाम सेवा का जीता-जागता उदाहरण होता है। वे



ज्यादा से ज्यादा अपना समय लोगों को स्वस्थ करने में लगाते हैं। स्वस्थ होने का अर्थ है बीमारियों से मुक्ति। बीमारी क्या है? क्या मेंम यानि आराम में नहीं होना। शारीरिक तौर पर अनेक बीमारियों के कारण हम अपने आपको अस्वस्थ महसूस करते हैं। मानसिक तौर पर हम अपने व्यवसाय की समस्याओं, घर की कठिनाईयों, सामाजिक परेणानियों या भावनात्मक तकलीफों के कारण भी अस्वस्थ होते हैं। बहुत से लोग आध्यात्मिक तौर पर भी हम अपने आपको जान नहीं पाते जिस करके वे परेणान रहते हैं क्योंकि उनके अंदर आत्मा-परमात्मा, जिंदगी के मकसद या मीत के बाद की जिंदगी के बारे में प्रण उठते रहते हैं। जब तक

हमें अर्थात् हमारी आत्मा को उनका उत्तर नहीं मिल जाता, तब तक वह बेचैन रहती है। इस प्रकार अपने आपको स्वस्थ करने के लिए हमें अपने आपको न सिर्फ शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी स्वस्थ रखना होगा। भौतिक शरीर के स्वास्थ्य के बारे में एक मनोरंजक कहावत है। यह कहा जाता है कि स्वास्थ्य में गिरावट के चार परिणाम होते हैं। पहला पसस (बीमार पड़ना), दूसरा चपसस (दवाईयों खाना), तीसरा इपसस (खर्च) और चौथा, कुछ एक मामलों में पसस (वसीयत लिखना)। मैं स्वस्थ होने के लिए एक विकल्प जोड़ना चाहूंगा, जो है जपसस अर्थात् (स्थिर होना)।

आईये! हम देखें कि ध्यान-अभ्यास अर्थात् स्थिर होने की कला, किस प्रकार से हमारे शरीर, मन, हमारी भावनाओं, आत्मा और पूरी दुनिया को स्वस्थ करने की शक्ति रखती है। आज की आधुनिक चिकित्सा प्रणाली भी इस नतीजे पर पहुँची है कि ध्यान-अभ्यास करने के अनेक लाभ हैं। इसका प्रतिदिन अभ्यास हमें आध्यात्मिक रूप से तो लाभ प्रदान करता ही है बल्कि इसके द्वारा हमें शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से भी अनेक लाभ मिलते हैं। चिकित्सा शोधकर्ताओं ने कुछ बीमारियों को हमारी मानसिक एवं भावनात्मक अवस्थाओं से भी जोड़ा है। बहुत खोज करने के बाद वे इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि जब हम मानसिक तनाव, भावनात्मक पीड़ा या उदासी के समय से गुजरते हैं तो हमारे शरीर की प्रतिरोधक शक्ति कम हो जाती है। जिससे कारण हम अनेक बीमारियों से ग्रस्त हो जाते हैं। डॉ. जॉन. क्रैवन द्वारा किये गए एक शोध के अनुसार ध्यान-अभ्यास करने वाले लोगों में तनाव की मात्रा कम पाई जाती है। ध्यान-अभ्यास

पर किये गए परीक्षणों में पाया गया है कि इससे तनाव संबंधी बीमारियों जैसे उच्च रक्तचाप, नींद न आना, दमा, दिल की धड़कन में अनियमितता आदि में सुधार हो जाता है। बहुत से चिकित्सा केन्द्रों एवं अस्पतालों में तनाव कम करने के लिए और कुछ एक बीमारियों का इलाज करने के लिए आजकल ध्यान-अभ्यास की कक्षाएँ भी लगाई जाती हैं। ध्यान-अभ्यास हमारे मन और हमारी भावनात्मक अवस्था को स्वस्थ करके हमारे शरीर की भी स्वस्थ रखता है। चिकित्सक अपने मरीजों का इलाज करते हुए, उन्हें बीमारियों से रोकथाम के लिए एवं अपने इलाज को अधिक असरदार बनाने के लिए ध्यान-अभ्यास में समय लगाने की सलाह दे सकते हैं। ध्यान-अभ्यास में प्रतिदिन कुछ समय देने से, उनके मरीज एक ऐसी स्वास्थ्य शक्ति के संपर्क में आ जायेंगे, जोकि उनके ज़िंदगी को बदल देगी और उन्हें राहत एवं धैर्य प्रदान करेगी। आईये आज विष्व डॉक्टर्स दिवस पर हम उन सभी लोगों का धन्यवाद करें जोकि हमें स्वस्थ रखने के लिए दिन-रात प्रयासरत हैं।

उत्तराखंड की लगभग 7000 करोड़ लागत की प्रस्तावित विभिन्न महत्वपूर्ण सड़क परियोजनाओं पर केन्द्र की सहमति

वेलकम इंडिया संवाददाता

देहरादून। केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित बैठक में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रतिभाग किया। बैठक में उत्तराखंड की लगभग 7000 करोड़ लागत की प्रस्तावित विभिन्न महत्वपूर्ण सड़क परियोजनाओं पर सहमति बनी।

मुख्यमंत्री ने इसके तहत पांच प्रमुख सड़क परियोजनाओं, राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्पर मार्गों के माध्यम से संपर्क विस्तार सहित अन्य महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर सहमति बनी है। हरिद्वार में आयोजित होने वाले कुंभ-2027 की तैयारियों एवं श्रद्धालुओं की सुगम आवाजाही के दृष्टिगत यह परियोजनाएं महत्वपूर्ण हैं। साथ ही यह प्रदेश के आधारभूत ढांचे को नई मजबूती प्रदान करते हुए सड़क संपर्क, पर्यटन, सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्रों तथा दूरस्थ अंचलों के विकास को भी नई गति देंगे। मुख्यमंत्री श्री



पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर उत्तराखंड से संबंधित सड़क एवं अवसंरचना विकास से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर विस्तृत विचार-विमर्श किया गया। मुख्यमंत्री ने राज्य की भौगोलिक परिस्थितियों, सीमांत क्षेत्रों की सामरिक एवं रणनीतिक महत्ता, तीर्थारटन, पर्यटन

तथा आपदा प्रबंधन की आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए राज्य में सुदृढ़ एवं आधुनिक सड़क नेटवर्क के विकास की आवश्यकता पर बल दिया।

उन्होंने राज्य के लंबित प्रस्तावों पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय का अनुरोध किया। केन्द्रीय सड़क अवसंरचना निधि के अंतर्गत वर्ष 2026-27 हेतु राज्य सरकार को लगभग 750 करोड़ लागत की परियोजनाओं की स्वीकृति पर

सहमति प्रदान की गई। इसके साथ ही एनएचओ के अंतर्गत पांच प्रमुख परियोजनाओं की स्वीकृति प्रदान की गई, जिनकी कुल अनुमानित लागत लगभग 2966 करोड़ है।

मुख्यमंत्री ने वर्ष 2025-26 तक की 530.11 करोड़ की लंबित प्रतिपूर्ति राशि शीघ्र अवमुक्त किए जाने का भी अनुरोध किया। उन्होंने आगामी अर्धकुंभ मेला 2027 के दृष्टिगत हरिद्वार बाईपास परियोजना को

समयबद्ध रूप से पूर्ण किए जाने का अनुरोध किया। उन्होंने कोटद्वार बाईपास परियोजना के कार्यों में भी तेजी लाने का अनुरोध किया। दोनों ही प्रस्तावों की सहमति प्रदान की गई। मुख्यमंत्री ने एनएच पर स्पर के माध्यम से अन्य मार्गों के संयोजन हेतु कुल परियोजनाओं के लिए लगभग 3000 करोड़ की सैद्धांतिक सहमति प्रदान किए जाने का अनुरोध किया, जिस पर केन्द्रीय मंत्री द्वारा सकारात्मक सहमति व्यक्त की गई।

इसके अतिरिक्त अल्मोड़ा सिकुड़ा बेंड से एनएच-309 तक टनल सहित मोटर मार्ग निर्माण हेतु लगभग 300 करोड़ की परियोजना पर चर्चा और सैद्धांतिक सहमति की गई। राज्य में आपदा प्रबंधन में सफल और कुशल कार्यों के दृष्टिगत मुख्यमंत्री ने यूएलएमएससी के माध्यम से भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों में उपचारात्मक कार्यों हेतु डीपीआर तैयार किए जाने हेतु एमओयू करने का अनुरोध किया, जिससे संवेदनशील क्षेत्रों में स्थायी एवं

वैज्ञानिक समाधान सुनिश्चित हो सके। मंत्रालय द्वारा इसे स्वीकृत किया गया है।

मुख्यमंत्री ने बीआरओ से संबंधित लंबित मामलों, विशेषकर ऋषिकेश-गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग के हिना-तेखला-नेताला-गरमपानी खंड की डीपीआर तथा जोशीमठ बाईपास मार्ग के संशोधित प्रस्तावों को शीघ्र स्वीकृति प्रदान किए जाने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि अत्यंत कम दरों पर प्राप्त निविदाओं के मामलों में अतिरिक्त परफॉर्मंस सिक्योरिटी की वर्तमान व्यवस्था में आवश्यक संशोधन किया जाए, जिससे पर्यटन क्षेत्रों में सड़क निर्माण एवं स्लोप ट्रीटमेंट कार्य समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण ढंग से संपन्न हो सकें। बैठक में केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री अजय टण्डा, सचिव लोक निर्माण विभाग डॉ. पंकज कुमार पांडेय, सचिव सड़क परिवहन श्री बृजेश कुमार संत, स्थानिक आयुक्त श्री अजय मिश्रा एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

मिशन शक्ति टीम ने सुलझाया पति-पत्नी का विवाद, समझौते के बाद साथ किया विदा



असदुल्लाह सिद्दीकी

जोगिया/सिद्धार्थनगर (वेलकम इंडिया)। थाना जोगिया उदयपुर की मिशन शक्ति टीम ने मंगलवार को पति-पत्नी के बीच लंबे समय से चल रहे विवाद का समाधान कर परिवार को बिखरने से बचा लिया। थानाध्यक्ष अभय सिंह के निर्देशन में टीम ने शिकायत मिलने पर दोनों पक्षों की काउंसिलिंग की और आपसी संवाद के माध्यम से मनमुटाव दूर कराया।

प्रभावी पत्नी धूपचंद, निवासी करहरही, थाना जोगिया उदयपुर की शिकायत की जांच के दौरान दोनों पक्षों को समझाया गया। काउंसिलिंग के बाद पति-पत्नी ने आपसी सहमति से साथ रहने का निर्णय लिया, जिसके बाद पुलिस ने दोनों को एक साथ विदा किया। कार्रवाई में उपनिरीक्षक आनंद कुमार शाही, हेड कांस्टेबल जितेंद्र सिंह, महिला हेड कांस्टेबल सत्या त्रिपाठी तथा महिला कांस्टेबल रानी विश्वकर्मा की प्रमुख भूमिका रही। मिशन शक्ति टीम की इस पहल की स्थानीय लोगों ने सराहा।

नवागत क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी से मिले नीमा पदाधिकारी, समस्याओं पर हुई चर्चा

असदुल्लाह सिद्दीकी

सिद्धार्थनगर (वेलकम इंडिया)। नेशनल इंटीग्रेटेड मेडिकल एसोसिएशन (नीमा) के पदाधिकारियों ने नवागत क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी डॉ. मीनू सोनी से शिष्टाचार भेंट कर उनका जनपद में स्वागत किया। इस दौरान आयुष चिकित्सकों की समस्याओं और झोलाछाप चिकित्सकों पर प्रभावी कार्रवाई को लेकर विस्तार से चर्चा हुई।

नीमा के संरक्षक डॉ. केपी पांडे ने डॉ. मीनू सोनी का संगठन के पदाधिकारियों से परिचय कराया। उन्होंने कहा कि नीमा से जुड़े सभी चिकित्सक विधिवत पंजीकृत हैं, इसके बावजूद कई बार उनके यहां अनावश्यक जांच टीम पहुंच जाती है। उन्होंने मांग की कि पंजीकृत आयुष चिकित्सकों को अनावश्यक रूप से परेशान न किया जाए तथा अपंजीकृत झोलाछाप चिकित्सकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। क्षेत्रीय



आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी डॉ. मीनू सोनी ने आश्वासन दिया कि पंजीकृत चिकित्सकों पर अनावश्यक छापेमारी नहीं होगी। उन्होंने कहा कि आयुर्वेद और यूनानी चिकित्सा की आड़ में मरीजों का शोषण करने वाले अपंजीकृत लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नीमा के अध्यक्ष डॉ. जावेद कमाल ने आयुष चिकित्सकों के पांच वर्षीय पंजीकरण का मुद्दा

उठाया। इस पर डॉ. मीनू सोनी ने बताया कि अब क्षेत्रीय कार्यालय से सभी आयुष चिकित्सकों का पंजीकरण पांच वर्ष के लिए किया जाएगा।

इस अवसर पर डॉ. आर.एन. जायसवाल, डॉ. मसूद अख्तर, डॉ. कमलेश मिश्रा, डॉ. अहमद हुसैन, डॉ. हाफिजुर रहमान और डॉ. रफीउद्दीन खां सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे।

नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, न्यायालय भेजा गया



असदुल्लाह सिद्दीकी

त्रिलोकपुर/सिद्धार्थनगर (वेलकम इंडिया)। थाना त्रिलोकपुर पुलिस ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में वांछित एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर मंगलवार को न्यायालय भेज दिया। पुलिस ने आवश्यक विधिक कार्रवाई पूरी करने के बाद आरोपी को न्यायालय में पेश किया।

प्रभारी निरीक्षक हरेकृष्ण उपाध्याय के निर्देशन में चौकी प्रभारी बिस्कोहर उपनिरीक्षक अमित कुमार शाही ने पुलिस टीम के साथ कार्रवाई

करते हुए थाना त्रिलोकपुर में दर्ज एक मामले में वांछित अभियुक्त अमित कुमार पुत्र किशन निवासी रेकहत, थाना देबरुआ को दोपेड़वा तिराहे के पास से गिरफ्तार किया।

पुलिस के अनुसार गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध नाबालिग से दुष्कर्म का मामला दर्ज है। गिरफ्तारी के बाद आवश्यक विधिक प्रक्रिया पूरी कर उसे न्यायालय भेज दिया गया। इस कार्रवाई में उपनिरीक्षक अमित कुमार शाही के साथ अरक्षी अजय यादव एवं राहुल यादव की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

पेपर लीक के विरोध में एनएसयूआई की बैठक, परीक्षा प्रणाली पर उठाए सवाल

असदुल्लाह सिद्दीकी

सिद्धार्थनगर (वेलकम इंडिया)। जिला कांग्रेस कार्यालय में मंगलवार को भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन (एनएसयूआई) की बैठक जिलाध्यक्ष मोहम्मद याकूब की अध्यक्षता में हुई। बैठक में यूपीएससी, आरआरबी, नीट सहित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक की घटनाओं पर चिंता जताते हुए केन्द्र सरकार की नीतियों की आलोचना की गई।

मोहम्मद याकूब ने कहा कि लगातार पेपर लीक होने से युवाओं का भविष्य प्रभावित हो रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि परीक्षाओं की पारदर्शिता पर सवाल खड़े हो रहे हैं और अभ्यर्थियों को मानसिक व आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

उन्होंने परीक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने और दोषियों पर सख्त



कार्रवाई की मांग की। बैठक को संबोधित करते हुए कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष (कार्यक्रम एवं प्रशासन) अनिल सिंह 'अनू बाबू' तथा अनुसूचित प्रकोष्ठ के नवनिर्वाचित जिलाध्यक्ष डॉ. प्रमोद कुमार ने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सरकार को ठोस कदम उठाने चाहिए। उन्होंने

आरोप लगाया कि यदि समय रहते प्रभावी सुधार नहीं किए गए तो छात्र आंदोलन तेज किया जाएगा। बैठक में शोकत अली, जुबेर अहमद, असमद अली, दुर्गा, हाफिजुर रहमान, सूरज कसौधन, लकी आनंद, आशुतोष जायसवाल, अभिषेक दुबे, इशराद अहमद समेत अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे।

सीएस ने पीएम द्वारा शिलान्यास की गयी परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की

देहरादून (वेलकम इंडिया)। मुख्य सचिव श्री आनंद बर्द्धन ने सचिवालय में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा शिलान्यास किए गए प्रोजेक्ट्स की प्रगति की समीक्षा की। मुख्य सचिव ने सभी 40 गतिमान परियोजनाओं की प्रगति की विस्तार से जानकारी ली। मुख्य सचिव ने सभी सम्बन्धित सचिवगणों को निर्देश दिए कि प्रोजेक्ट्स की नियमित समीक्षा कर प्रगति रिपोर्ट नियमित रूप से पोर्टल पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने सम्बन्धित विभागों को प्रोजेक्ट्स निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत पूर्ण किए जाने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि पर्यटन विभाग के अंतर्गत महासू देवता, हनोल में समग्र बुनियादी ढांचे की निर्माण एवं जाणेश्वर धाम बर्द्धन से सम्बन्धित कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर लेते हुए प्रतिदिन समीक्षा करते हुए निर्धारित समयसीमा के भीतर कार्य पूर्ण कराया जाए। उन्होंने शहरी विकास विभाग के अंतर्गत संचालित देहरादून में जलपूर्ति, सीवर और जल निकासी प्रणाली के विकास कार्य को भी शीघ्र पूर्ण कराए

जाने हेतु नियमित मॉनिटरिंग किए जाने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने ऊर्जा विभाग को लखवाड बहुदेशीय परियोजना (300 मेगावाट), 220 केवी बनबसा सबस्टेशन (100 एमवीए) और उससे जुड़ी ट्रांसमिशन लाइन, चमोली में 400 केवी पीपलकोटी स्विचिंग सबस्टेशन और उससे जुड़ी ट्रांसमिशन लाइन सहित टिहरी जिले के घनसाली में 220 केवी घनसाली सबस्टेशन के निर्माण कार्यों में भी तेजी लाने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने कहा कि जिन परियोजनाओं का कार्य लगभग पूर्ण होने की कगार पर है, ऐसे प्रोजेक्ट्स को विभाग प्राथमिकता पर लेते हुए शीघ्र पूर्ण कराए। उन्होंने 13 जनपदों के लिए 73 पेयजल आपूर्ति परियोजनाओं, पीएमजीएसवाई के अंतर्गत 133 सड़कों (96 प्रतिशत पूर्ण) और 151 पुलों के निर्माण कार्य (97 प्रतिशत पूर्ण) सहित नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत ऊधमसिंह नगर में नदी पुनर्जीवन कार्य (98 प्रतिशत) जैसे कार्यों को शीघ्र पूर्ण कराए जाने के निर्देश दिए।

जिला कारागार का त्रैमासिक निरीक्षण, बंदियों को बांटी गई शैक्षणिक किट व प्रमाण-पत्र

असदुल्लाह सिद्दीकी

सिद्धार्थनगर (वेलकम इंडिया)। जिला कारागार का त्रैमासिक निरीक्षण मंगलवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने संयुक्त रूप से किया। इस दौरान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव, बेसिक शिक्षा अधिकारी, विजिटर बोर्ड के सदस्य समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने पुरुष एवं महिला बैरकों, चिकित्सालय, भोजनालय, रसोईघर, स्वच्छता व्यवस्था, पेयजल, सुरक्षा व्यवस्था और बंदियों को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं का जायजा लिया। बंदियों से संवाद कर उनकी समस्याएं सुनीं और संबंधित अधिकारियों को उनके शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए। अधिकारियों ने कारागार में संचालित शिक्षा, कौशल



विकास, योग एवं पुस्तकालय जैसी सुधारात्मक गतिविधियों की सराहना करते हुए कहा कि कारागार केवल दंड का स्थान नहीं, बल्कि सुधार और पुनर्वास का केंद्र है। शिक्षा के माध्यम से बंदियों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। निरीक्षण के बाद आयोजित कार्यक्रम में शिव नाथर फाउंडेशन के सहयोग से अध्ययनरत बंदियों को शैक्षणिक

किट और प्रमाण-पत्र वितरित किए गए। जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने बंदियों को शिक्षा के महत्व से अवगत कराते हुए निरंतर अध्ययन के लिए प्रेरित किया। जिलाधिकारी ने कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप कारागारों में सुधारात्मक एवं पुनर्वास संबंधी गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक ने अनुशासन, सकारात्मक सोच और शिक्षा को जीवन

में बदलाव का आधार बताते हुए बंदियों से रचनात्मक गतिविधियों में भागीदारी का आह्वान किया। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव ने बंदियों को निःशुल्क विधिक सहायता की जानकारी दी, जबकि बेसिक शिक्षा अधिकारी ने शैक्षणिक गतिविधियों की सराहना करते हुए हरसंभव सहयोग का भरोसा दिलाया।

सड़क पर निराश्रित महिला या बच्चा दिखे तो तुरंत दें सूचना, एक कॉल बचा सकती है जीवन

मयूर खान

आगरा (वेलकम इंडिया)। आगरा में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निराश्रित, बेसहारा एवं संकटग्रस्त महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा तथा पुनर्वास के लिए विशेष अभियान संचालित किया जा रहा है। अभियान के तहत आमजन से अपील की गई है कि यदि सड़क, फुटपाथ, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड अथवा किसी सार्वजनिक स्थान पर कोई निराश्रित महिला या बच्चा दिखाई दे तो इसकी सूचना तत्काल महिला

हेल्पलाइन 181 अथवा चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 पर दें। जिला प्रोबेशन अधिकारी ने बताया कि प्राप्त सूचना पर विभाग की रेस्क्यू टीम तत्काल मौके पर पहुंचकर संबंधित महिला या बच्चे को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाएगी तथा आवश्यकतानुसार चिकित्सा सहायता, काउंसिलिंग, आश्रय एवं पुनर्वास की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करेगी। महिलाओं एवं बच्चों के सुरक्षित रेस्क्यू के लिए विशेष रेस्क्यू वाहन भी उपलब्ध कराए गए हैं। उन्होंने कहा कि समाज के



प्रत्येक नागरिक की सहभागिता इस अभियान की सफलता के लिए

आवश्यक है। समय पर दी गई सूचना किसी जरूरतमंद महिला या

● महिला हेल्पलाइन 181 और चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 पर दें सूचना, तुरंत पहुंचेगी रेस्क्यू टीम, निराश्रित महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए शासन का चलाया जा रहा विशेष अभियान

बच्चे को सुरक्षित जीवन, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सम्मानजनक भविष्य प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।

जिला प्रोबेशन अधिकारी ने जनपदवासियों से अपील की है कि किसी भी निराश्रित, बेसहारा अथवा

संकटग्रस्त महिला एवं बच्चे के संबंध में तत्काल महिला हेल्पलाइन 181, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 अथवा जिला प्रोबेशन अधिकारी, आगरा के मोबाइल नंबर 75802406 पर सूचना दें, ताकि उन्हें शीघ्र सहायता एवं पुनर्वास उपलब्ध कराया जा सके।

पत्रकार से 29 हजार की लूट, असलहा लहराकर भागे बदमाश बुद्धा पार्क के पास दिनदहाड़े वारदात, जांच में जुटी पुलिस



में बदलाव का आधार बताते हुए बंदियों से रचनात्मक गतिविधियों में भागीदारी का आह्वान किया। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव ने बंदियों को निःशुल्क विधिक सहायता की जानकारी दी, जबकि बेसिक शिक्षा अधिकारी ने शैक्षणिक गतिविधियों की सराहना करते हुए हरसंभव सहयोग का भरोसा दिलाया।

असदुल्लाह सिद्दीकी

सिद्धार्थनगर (वेलकम इंडिया)। सदर थाना क्षेत्र के अशोक मार्ग स्थित बुद्धा पार्क के पास मंगलवार को दिनदहाड़े बाइक सवार दो बदमाशों ने एक पत्रकार को रोककर 29 हजार रुपये लूट लिए। विरोध करने पर बदमाशों ने असलहा लहराया और सांडी तिराहे की तरफ भाग निकले। पीड़ित ने थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। इलाखी नगर निवासी आसिफ इकबाल स्थानीय स्तर पर पत्रकार हैं। पुलिस को दी तहरीर में उन्होंने बताया कि मंगलवार दोपहर करीब 2:40 बजे वह अपने साथी अम्बर प्रसाद के साथ बाइक से अशोक मार्ग होते हुए कार्यालय जा रहे थे।



जैसे ही वह बुद्धा पार्क के पास पहुंचे, तभी एक बाइक पर सवार दो अज्ञात बदमाशों ने उनकी बाइक को आगे से रोक लिया। बदमाशों ने उन्हें धक्का देकर बाइक सहित जमीन पर गिरा दिया। इसके बाद बदमाशों ने पत्रकार की शर्ट की जेब में रखे 29 हजार रुपये (सभी 500 के नोट) जबरन छीन लिए। बाइक पर पीछे बैठे साथी अम्बर प्रसाद ने बदमाशों को पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन बदमाशों ने असलहा वार दिया और धमकी देते हुए सांडी तिराहे की ओर फरार हो गए। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस मामले की छानबीन कर रही है।

महज 9 वर्ष की आयु में श्वेतिमा माधव प्रिया ने रचा विश्व कीर्तिमान: एशिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज हुआ नाम

बनीं विश्व की सबसे कम आयु की अंतरराष्ट्रीय बाल भागवत कथा वाचिका

डॉ. शंभु पंवार

नई दिल्ली(वेलकम इंडिया)। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जनपद के बेलीपार क्षेत्र स्थित ग्राम भस्मा की प्रतिभाशाली बाल व्यास श्वेतिमा माधव प्रिया ने मात्र 9 वर्ष की आयु में विश्व स्तर पर ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल कर भारत का गौरव बढ़ाया है।

एशिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने उन्हें विश्व की सबसे कम आयु की अंतरराष्ट्रीय बाल भागवत कथा वाचिका के रूप में आधिकारिक मान्यता प्रदान करते हुए उनका नाम विश्व रिकॉर्ड में दर्ज किया है। संस्था द्वारा जारी प्रमाणपत्र के



अनुसार श्वेतिमा माधव प्रिया ने अल्पयु में ही 36 श्रीमद्भागवत कथा सप्ताह तथा 100 से अधिक धार्मिक, आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक आयोजनों में कथा वाचन कर सनातन

संस्कृति, भारतीय आध्यात्मिक परंपरा, नैतिक मूल्यों, मानवता और विश्व बंधुत्व का संदेश देश-विदेश तक पहुंचाया है। उनकी प्रभावशाली वाणी, शास्त्रों का गहन अध्ययन तथा ओजस्वी प्रस्तुति ने उन्हें राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विशिष्ट पहचान दिलाई है।

श्वेतिमा माधव प्रिया, सौहार्द शिरोमणि संत डॉ. सौरभ पाण्डेय एवं देहदानी डॉ. रागिनी पाण्डेय की सुपुत्री हैं। उनकी इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर देशभर के साहित्यकारों, शिक्षाविदों, समाजसेवियों, पत्रकारों एवं विभिन्न प्रतिष्ठित संस्थाओं ने हर्ष व्यक्त करते हुए उन्हें उच्चल भविष्य

की शुभकामनाएँ प्रेषित की हैं। शुभकामनाएँ देने वालों में प्रख्यात उद्यमी एवं वरिष्ठ साहित्यकार डॉ. वी.एन. गौड़, प्रसिद्ध समाजसेवी डॉ. इन्द्रजीत शर्मा, वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर, अंतरराष्ट्रीय लेखक एवं पत्रकार-विचारक डॉ. शंभु पंवार, गीतांजलि काव्य प्रसार मंच की राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं प्रसिद्ध लेखिका, साहित्यकार डॉ. गीतांजलि नोरज अरोड़ा 'गीत', उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के सदस्य एवं शिक्षाविद डॉ. अहसान अहमद, वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर एवं लेखिका डॉ. निक्की शर्मा 'रश्मि', कथा कुज साहित्य परिवार के संस्थापक डॉ. गोविंद गुप्ता,

पाठ्यपुस्तक लेखिका एवं शिक्षाविद डॉ. निशा अग्रवाल, वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर डॉ. विनय श्रीवास्तव, वरिष्ठ पत्रकार कृपाशंकर राय, वरिष्ठ साहित्यकार डॉ. सत्यवीर निराला, रेव. डॉ. जितेंद्र सिंह, डॉ. टीकम सोनी सहित देशभर की अनेक प्रतिष्ठित साहित्यिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक संस्थाओं के प्रतिनिधि और प्रबुद्धजन शामिल हैं। श्वेतिमा माधव प्रिया की यह उपलब्धि न केवल गोरखपुर और उत्तर प्रदेश, बल्कि संपूर्ण देश के लिए गौरव का विषय मानी जा रही है। इतनी कम आयु में आध्यात्मिक क्षेत्र में स्थापित यह विश्व कीर्तिमान नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा का स्रोत है।

पाइपलाइन परियोजना में अनियमितता के आरोपों पर जल निगम की टीम ने किया स्थलीय निरीक्षण

वेलकम इंडिया संवाददाता

जहांगीराबाद। नगर में चल रही पाइपलाइन परियोजना अब प्रशासनिक जांच के घेरे में आ गई है। परियोजना के तहत कार्यों की गुणवत्ता और भुगतान प्रक्रिया में बरती गई कथित अनियमितताओं को लेकर उठ रहे सवाल के बाद, जल निगम की टीम ने सोमवार को मौके पर पहुंचकर स्थलीय निरीक्षण किया। जनकारी के अनुसार विवाद की शुरुआत वार्ड संख्या-6 के मोहल्ला गुसाईयान से हुई। वार्ड संख्या-6 के सभासद संजय कोरी ने आरोप लगाया था कि क्षेत्र में पाइपलाइन बिछाने का कार्य या तो अधूरा है या फिर मानकों के अनुपम नहीं किया गया है। इसके बावजूद भी परियोजना का भुगतान तक करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। शिकायत में मुख्य



रूप से पाइपों की गुणवत्ता, तकनीकी खामियों और खुदाई के बाद सड़कों की मरम्मत न किए जाने के मुद्दे उठाए गए थे। मामले को गंभीरता को देखते हुए नगर विकास विभाग के विशेष सचिव सत्यप्रकाश पटेल ने डीएम बुलंदशहर को जांच के निर्देश दिए थे। इसी क्रम में सोमवार दोपहर जल निगम के सहायक अभियंता (ई) प्रवीण कुमार ने वार्ड सभासद संजय कोरी और शिकायतकर्ताओं के साथ मौके पर पहुंचकर वस्तुस्थिति का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान

कुछ स्थानों पर खुदाई के बाद सड़क मरम्मत कार्य अधूरा पाया गया। इन तकनीकी कमियों को स्वीकार करते हुए सहायक अभियंता ने संबंधित अधिकारियों और कार्यदायी संस्था को अविलंब मरम्मत कार्य पूरा करने के कड़े निर्देश दिए हैं। सहायक अभियंता प्रवीण कुमार ने बताया कि निरीक्षण की विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर उच्चधिकारियों को सौंपी जाएगी। अब स्थानीय निवासियों और जनप्रतिनिधियों की नजरें इस रिपोर्ट पर टिकी हैं।

जिला जज के नेतृत्व में मॉनिटरिंग सेल की मासिक गोष्ठी, डीएम व एसएसपी ने बाल सम्प्रेक्षण गृह और जिला कारागार का किया औचक निरीक्षण



वेलकम इंडिया संवाददाता

बुलंदशहर। मंगलवार को जिला जज संजय सिंह, जिलाधिकारी कुमार हर्ष, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार सिंह ने संयुक्त रूप से मॉनिटरिंग सेल की मासिक गोष्ठी आयोजित की गयी तथा सम्बन्धित को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये। इसके उपरान्त जिला जज संजय सिंह के नेतृत्व में जिलाधिकारी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा

राजकीय सम्प्रेक्षण गृह (किशोर) का औचक निरीक्षण करते हुए बाल अपचारियों को सम्प्रेक्षण गृह प्रशासन द्वारा दी जा रही सुविधाओं का जायजा लेते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए।

तत्पश्चात जिला कारागार का निरीक्षण कर दी जा रही सुविधाओं का जायजा लिया गया तथा सम्बन्धित को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गये। इस अवसर पर सम्बन्धित अधिकारीगण मौजूद रहे।

सोनी टीवी के लोकप्रिय गेम शो में छाई डॉ. ईशा भारद्वाज

'बरसाने की बहू' ने जीता दर्शकों का दिल, स्वरचित कविताओं से बटोरी खूब वाहवाही

डॉ. शंभु पंवार

नई दिल्ली(वेलकम इंडिया)। शिक्षाविद, कवयित्री, लेखिका, कथक पारंगत एवं समाजसेवी डॉ. ईशा भारद्वाज (दिल्ली) ने सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन के लोकप्रिय गेम शो 'तुम होना घर की सुपरस्टार' में अपनी शानदार प्रस्तुति से राष्ट्रीय स्तर पर एक बार फिर अपनी विशिष्ट पहचान दर्ज कराई। 'बरसाने की बहू' के रूप में उनकी सजीव प्रस्तुति, आत्मविश्वास से भरपूर व्यक्तित्व और सहज अभिव्यक्ति पूरे कार्यक्रम का प्रमुख आकर्षण रही। लोकप्रिय अभिनेता एवं होस्ट राजीव खंडेलवाल के साथ प्रसारित इस मनोरंजक शो में डॉ. ईशा भारद्वाज ने विभिन्न रोचक गेम्स में उत्साहपूर्वक भाग लेते हुए अपनी बुद्धिमत्ता, हाजरजवाबी और सकारात्मक ऊर्जा से दर्शकों का भरपूर



मनोरंजन किया। उनकी स्वाभाविक शैली और प्रभावशाली उपस्थिति ने कार्यक्रम में अलग ही छाप छोड़ी। कार्यक्रम का सबसे यादगार क्षण तब आया जब डॉ. ईशा भारद्वाज ने अपनी

स्वरचित कविताओं का संस्वर पाठ किया। संवेदनाओं से ओतप्रोत उनकी रचनाओं ने दर्शकों और मंच पर उपस्थित सभी लोगों को भावविभोर कर दिया। उनकी साहित्यिक अभिव्यक्ति को जीवंत सराहना मिली और उन्होंने यह सिद्ध किया कि वे केवल मंचीय प्रस्तुति ही नहीं, बल्कि साहित्य सृजन में भी समान रूप से दक्ष हैं। उल्लेखनीय है कि डॉ. ईशा भारद्वाज इससे पूर्व भी 'Wheel of Fortune with Akshay Kumar', 'सबसे Smart Kaun?' तथा 'DID' जैसे राष्ट्रीय स्तर के लोकप्रिय टेलीविजन कार्यक्रमों में अपनी प्रतिभा का प्रभावशाली प्रदर्शन कर चुकी हैं। विभिन्न राष्ट्रीय मंचों पर उनकी निरंतर उपस्थिति उनके बहुआयामी व्यक्तित्व, रचनात्मक प्रतिभा और निरंतर प्रगति की सशक्त गवाही देती है। अपने अनुभव साझा

करते हुए डॉ. ईशा भारद्वाज ने कहा कि यह मंच उनके लिए केवल एक गेम शो नहीं, बल्कि सीख, संवाद और आत्म-अभिव्यक्ति का अविस्मरणीय अवसर रहा। इस मंच के माध्यम से उन्हें अपनी संस्कृति, साहित्य और भारतीय जीवन मूल्यों को देशभर के दर्शकों तक पहुंचाने का सौभाग्य मिला। शो का परिणाम चाहे जो भी रहा हो, लेकिन डॉ. ईशा भारद्वाज अपनी गरिमायुगी प्रस्तुति, साहित्यिक प्रतिभा और आत्मीय व्यक्तित्व से दर्शकों का दिल जीतने में सफल रहीं। उनकी इस उपलब्धि पर साहित्यकारों, शिक्षाविदों, गणमान्य नागरिकों एवं शुभचिंतकों ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए उन्हें हार्दिक बधाई और शुभकामनाएँ दीं। सभी ने विश्वास व्यक्त किया कि वे भविष्य में भी राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय मंचों पर अपनी प्रतिभा का परचम लहराते हुए देश का नाम रोशन करती रहेंगी।

नवनिर्मित मंदिर में शिव परिवार की प्राण प्रतिष्ठा विधि-विधान से की गई



वेलकम इंडिया संवाददाता

बुलंदशहर। अहार क्षेत्र के गांव बामनपुर में नवनिर्मित मंदिर में शिव परिवार की प्राण प्रतिष्ठा विधि-विधान से की गई। सुबह करीब आठ बजे पंडित राहुल शर्मा ने मंत्रोच्चारण करके मंदिर गर्भगृह में शिवलिंग, मां पार्वती और श्री गणेश भगवान की मूर्तियों को प्राण प्रतिष्ठा

कराई। इससे पहले ग्रामीण बैड बाजा और डी जे बजाते हुए मां अर्चिका देवी गंगा घाट पर पहुंचे और शिव परिवार को स्नान कराया गया। इस अवसर पर समाजसेवी धीरज राणा, बाल किशन सिंह, पप्पू सिंह, रिकू, अशोक, मुकेश आदि मौजूद रहे। मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद श्रीराम चरित मानस पाठ शुरू किया गया है।

आमजन में पर्यावरण जागरूकता से आयेगी थार में हरियाली की बहार: बोहरा

वेलकम इंडिया ब्यूरो

बाड़मेर राजस्थान। जिला मुख्यालय से महज 6 किलोमीटर दूर राष्ट्रीय राजमार्ग-68 अहमदाबाद मार्ग पर स्थित राजस्व गांव सांसियों का तला के सर्वांगीण विकास को लेकर जन कल्याण संस्थान, बाड़मेर की ओर से संचालित अभियान ग्रामोदय में पर्यावरण गतिविधि के तहत मंगलवार को अभियान प्रेरक मुकेश अमन के नेतृत्व में ग्रामीणों को 200 पौधे वितरित कर पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक किया गया। साथ ही विद्यालय में पौधारोपण किया गया।



संस्थान के सदस्य राजेश जोशी ने बताया कि सांसियों का तला राजस्व गांव को हरा-भरा बनाने को लेकर पिछले कई वर्षों से अभियान ग्रामोदय के माध्यम से सतत पौधारोपण का कार्य किया जा रहा है। जिस कड़ी में मंगलवार को सांसियों का तला में ग्रामीणों को 200 पौधे निःशुल्क वितरित किये गये। तथा पर्यावरण संरक्षण से आमजन को संकल्प दिलाया गया। पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता आयेगी। इसी

जागरूकता से थार में हरियाली की बहार व रौनक आयेगी। इस दौरान भारतीय एयरटेल के प्रतिनिधि हितेश तिवारी, ओम्प्रकाश सरगर्, विशाल सर, मुकेश अमन, राजेश जोशी, डा.लूणाम सेजु, रूपाराम, मनोज, अमिताभ, साजन, दीपक, लूणाराम आदि बड़ी संख्या में ग्रामीण व बच्चे उपस्थित रहे।

बिजली समस्या को लेकर एक्सईन को सौंपा ज्ञापन



वेलकम इंडिया संवाददाता

डिबाई, (बुलंदशहर)। नगर में बिजली की भारी किल्लत को लेकर उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल डिबाई के पदाधिकारियों ने एक ज्ञापन अधिशासी अभियंता राहुल रब बोधी को दीपक गुप्ता के नेतृत्व में दिया जिसमें कम वोल्टेज, भारी ट्रिपिंग असीमित कटौती, फोन पर किसी भी कर्मचारी द्वारा जबाब न देना आदि समस्याओं का जिक्र ज्ञापन में है। अधिशासी अभियंता ने बताया कि वर्तमान में एक नंबर फीडर पर अधिक लोड होने के कारण बार-बार ट्रिपिंग की समस्या आ रही है। इस समस्या के स्थायी समाधान के लिए नई लाइन तैयार की जा रही है। नई लाइन का कार्य

लगभग पूरा हो चुका है और इसके चालू होते ही लोड अलग-अलग फीडरों में बंट जाएगा, जिससे ट्रिपिंग की समस्या काफी हद तक समाप्त हो जाएगी। उन्होंने उम्मीद जताई कि अगले दो दिनों में बिजली व्यवस्था सामान्य हो जाएगी और उपभोक्ताओं को निर्बाध आपूर्ति मिल सकेगी। 2 दिन में ईंछावरी रोड पर एक लाइन पड़ रही है जिससे डिबाई टाउन वन जिस पर सर्वाधिक लोड है वह 2 भागों में विभक्त हो जाएगा जिससे 60 प्रतिशत समस्या हल हो जाएगी। कसेरे फीडर के लिये अलग ट्रांसफर रख गया है एक सप्ताह में वह भी समस्या हल हो जाएगी। ज्ञापन देने वालों में नवीन ठाकुर, विठू गोस्वामी, सनी सिंघल, जितिन साई, बंटी अग्रवाल आदि रहे।

जनसुनवाई में दो समस्याओं का हुआ तत्काल समाधान

अपर नगरायुक्त ने लाइट व अतिक्रमण सम्बंधी समस्याओं के निराकरण हेतु अधिकारियों को दिए निर्देश

वेलकम इंडिया ब्यूरो

सहारनपुर। नगर निगम की जनसुनवाई में आज स्ट्रीट लाइट, अतिक्रमण तथा नाली व सड़कों की सफाई के सम्बंध में 10 समस्याएं आयी जिनमें से दो समस्याओं का अपर नगरायुक्त ने तुरंत समाधान करा दिया। बाकि समस्याओं के निराकरण के लिए सम्बंधित विभागों के अधिकारियों को स्थलीय निरीक्षण कर कार्रवाई के निर्देश दिए गए।



वार्ड 39 हिम्मत नगर के भूप सिंह आर्य ने हिम्मत नगर में तथा वार्ड 41 शारदा नगर निवासी राहुल शर्मा ने शारदा नगर में नाली सफाई के लिए प्रार्थना पत्र दिए जिस पर अपर नगरायुक्त मृत्युंजय ने क्षेत्रीय सफाई निरीक्षकों व सफाई मित्रों को भेजकर नालियों की सफाई कराते हुए समस्या का समाधान करा दिया। इसी कड़ी में वार्ड 13 आकाशपुरम कॉलोनी निवासी अंशु अग्रवाल ने चकहेट्टी में परग डेरी के पास नाली की सफाई के लिए, वार्ड संख्या 27 लक्की परिसर निवासी मोहर सिंह ने लक्की परिसर के निकट

न्यू गोपाल नगर निवासी अक्षय राजदेव ने न्यू गोपाल नगर में किये गए अतिक्रमण को हटाने के लिए प्रार्थना पत्र दिया। वार्ड 33 द्वारिकापुरी कॉलोनी के चौ. विक्रम सिंह ने कॉलोनी की स्ट्रीट लाइट ठीक कराने वार्ड 11 के राजकुमार ने पानी की पाइप लाइन ठीक कराने के लिए प्रार्थना पत्र दिया। जिस पर सम्बंधित विभाग के अधिकारियों को स्थलीय निरीक्षण कर कार्रवाई के निर्देश दिए गए।

बेमौसम बारिश से बेहाल किसान, सड़कों पर मक्का सुखाने को मजबूर, हादसों का बढ़ा खतरा

वेलकम इंडिया संवाददाता

जहांगीराबाद। क्षेत्र में बदलते मौसम के पिजाज ने किसानों की कम्तर तोड़ दी है। बेमौसम हो रही बारिश और उसके बाद खिली तेज धूप के कारण मक्के की फसल में अत्यधिक नमी बनी हुई है। फसल को सड़ने और खराब होने से बचाने की जदोजहद में किसान अब मक्का सुखाने के लिए सड़कों और संपर्क मार्गों का सहारा ले रहे हैं।



इस मजबूरी ने न केवल यातायात व्यवस्था को प्रभावित किया है, बल्कि सड़क हादसों की आशंका भी बढ़ा दी है। किसानों का कहना है कि खेत से कटी फसल में बारिश की वजह से नमी बनी हुई है। यदि इस मक्का को तत्काल नहीं सुखाया गया, तो दानों में फफूंद लगने और रंग काला पड़ने का खतरा है। इससे उपज की गुणवत्ता खराब हो

जाएगी और बाजार में उन्हें फसल का उचित दाम नहीं मिल पाएगा। खुले स्थानों की कमी के चलते,

मजबूरी में किसान अपनी फसल सड़क के किनारों और मुख्य मार्गों की पटरियों पर फैला रहे हैं। सुबह

धूप निकलते ही किसान फसल सुखाने में जुट जाते हैं और शाम को उसे समेट लेते हैं। सड़कों पर फैली मक्के की फसल राहगीरों, विशेषकर दोपहिया वाहन चालकों के लिए बड़ी मुसीबत बन गई है।

मक्के के दानों पर टायर फिसलने से संतुलन बिगड़ने और दुर्घटनाओं का अंदेश बना रहता है। स्थानीय लोगों के अनुसार, कई बार वाहन चालक अचानक ब्रेक लगाने के चक्कर में चोटिल हो चुके हैं।

ग्रामीणों ने चिंता जताई है कि यदि इस समस्या का कोई सुरक्षित विकल्प नहीं निकाला गया, तो किसी भी समय कोई बड़ी दुर्घटना घट सकती है।

वहीं कृषि विशेषज्ञों के अनुसार, मौसम का यह उतार-चढ़ाव खरीफ की फसलों के लिए हानिकारक है। यदि अनेक वाले दिनों में फिर बारिश होती है, तो मक्के के साथ-साथ अन्य

फसलों को भी व्यापक नुकसान हो सकता है। विशेषज्ञों ने किसानों को मौसम के पूर्वानुमान पर नजर रखने और फसल को सुखाने के लिए सुरक्षित या कवर्ड (ढके हुए) स्थानों का उपयोग करने की सलाह दी है। तेज धूप, उमस और रुक-रुककर हो रही बारिश के कारण क्षेत्र में मौसमी बीमारियों ने भी पैर पसारने शुरू कर दिए हैं।

सरकारी और निजी अस्पतालों में बुखार, वायरल संक्रमण, सर्दी-जुकाम और पेट संबंधी समस्याओं से पीड़ित मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ है।

जिस पर चिकित्सकों ने हमेशा साफ और खूबसूरत पानी पीने, खुले में बिकने वाली सामग्री और बासी भोजन का सेवन से बचने, तापमान में बदलाव के प्रति सावधानी बरतने और खान-पान में शुद्धता बनाए रखने की सलाह दी है।

समस्त सीओ द्वारा देहात सर्किल के समस्त थानों में प्रातःकालीन गणना कर पुलिस कर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए



वेलकम इंडिया संवाददाता

बुलंदशहर। मंगलवार को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार सिंह के निर्देशन में व पुलिस अधीक्षक ग्रामीण अंतरिक्ष जैन के कुशल पर्यवेक्षण में समस्त क्षेत्राधिकारियों द्वारा देहात सर्किल के समस्त थानों में प्रातःकालीन गणना एवं स्वच्छता अभियान कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान पुलिस कर्मियों को अनुशासन, जनसेवा एवं कार्यकुशलता से संबंधित आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।



कार्यवाही समवर्द्ध रूप से पूर्ण करने, जनसुनवाई को सुदृढ़ बनाए रखने तथा साइबर अपराधों में 'गोल्डन आवर' का लाभ लेते हुए त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया।

इसके उपरांत संबंधित थाना परिसरों का निरीक्षण कर साफ-सफाई एवं कार्यालयीय व्यवस्थाओं

का जायजा लिया गया। मिशन शक्ति केंद्र एवं साइबर सेल का निरीक्षण कर अभिलेखों के सुव्यवस्थित रख-रखाव तथा शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण हेतु आवश्यक निर्देश दिए गए। कार्यक्रम के दौरान पर्यावरण संरक्षण एवं स्वच्छता बनाए रखने हेतु सभी पुलिस कर्मियों को प्रेरित किया गया।

विधायक निधि और आरोपों पर डॉ. मंजू सिवाच का जवाब, कराए गए विकास कार्यों की सूची भी जारी

अनिल वशिष्ठ

मोदीनगर (वेलकम इंडिया)। मोदीनगर विधायक डॉ. मंजू सिवाच ने सोमवार को आयोजित प्रेस वार्ता में विधायक निधि के उपयोग, कबड्डी प्रतियोगिता तथा सोशल मीडिया पर लगाए जा रहे विभिन्न आरोपों का खंडन किया। उन्होंने कहा कि कुछ लोग उनकी छवि धूमिल करने के उद्देश्य से भ्रामक प्रचार कर रहे हैं, जबकि उन्होंने अपने कार्यकाल में विधानसभा क्षेत्र में जनहित के अनेक विकास कार्य कराए हैं।

डॉ. मंजू सिवाच ने कहा कि वह पिछले दस वर्षों से लगातार समाजसेवा

और विकास कार्यों में जुटी हैं तथा आगे भी क्षेत्र के विकास के लिए पूरी निष्ठा से कार्य करती रहेंगी। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोग और कुछ सोशल मीडिया पत्रकार मिलकर उनके खिलाफ दुष्प्रचार कर रहे हैं, जो निन्दनीय है। प्रेस वार्ता में विधायक के पति डॉ. देवेन्द्र सिवाच ने भी अपनी बात रखते हुए कहा कि उन्होंने वर्षों से अपने निजी संसाधनों से अनेक सामाजिक कार्य किए हैं। उन्होंने दावा किया कि जीवन अस्पताल के माध्यम से कई शिक्षकों के चेतन का भुगतान भी अपने निजी फंड से करते रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें भूमि कारोबार अथवा किसी माफिकता



गतिविधि से जोड़कर जो आरोप लगाए जा रहे हैं, वे पूरी तरह निराधार हैं। उनका कहना था कि उनका किसी अवैध भूमि कारोबार से कोई संबंध नहीं है और वे केवल जनता की सेवा के उद्देश्य से कार्य कर रहे हैं। विधायक डॉ. मंजू सिवाच ने अपने कार्यकाल में विधायक निधि से कराए गए विकास

कार्यों की सूची भी जारी की। सूची के अनुसार विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न विद्यालयों में प्रार्थना स्थल, शौचालय, अथवा भूमि कारोबार से कोई संबंध नहीं है और वे केवल जनता की सेवा के उद्देश्य से कार्य कर रहे हैं। विधायक डॉ. मंजू सिवाच ने अपने कार्यकाल में विधायक निधि से कराए गए विकास

भनेड़ा, अतरौली, लोरी, चूड़ीवाला, पतला, निवाड़ी, गाड़ना, मतीर, फरीदनगर, गोविंदपुरी, सिखेड़ा हजारी सहित कई गांवों और नगर पंचायतों के विद्यालय शामिल हैं। विधायक ने दावा किया कि इन कार्यों पर करोड़ों रुपये की लागत से शिक्षा और आधारभूत सुविधाओं का विकास कराया गया है। उन्होंने कहा कि इन विकास कार्यों के बावजूद उनकी छवि खराब करने के लिए दुष्प्रचार किया जा रहा है, जिसके चलते उन्हें प्रेस वार्ता कर तथ्य सार्वजनिक करने पड़े। वहीं डॉ. देवेन्द्र सिवाच ने अपने निजी फंड से कराए गए कार्यों का भी विवरण प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि फजलगढ़ के स्कूल

में बिजली कनेक्शन, चूड़ीवाला स्कूल में 42 पंखों की व्यवस्था, पतला इंटर कॉलेज में टाइल्स एवं लैब निर्माण, बाल सेवा समिति और लक्ष्य पाठशाला को सहयोग, सर रोड गोविंदपुरी, फरीदनगर और गदाना के सरस्वती शिशु मंदिर विद्यालयों में कक्ष निर्माण तथा अन्य कई शैक्षणिक संस्थानों में आर्थिक सहयोग दिया गया है। डॉ. देवेन्द्र सिवाच ने आरोप लगाया कि कुछ लोग सोशल मीडिया के माध्यम से उनके खिलाफ दुष्प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो लोग उन पर सवाल उठा रहे हैं, उन्हें पहले अपने कार्यकाल में किए गए कार्यों का भी जनता के सामने हिसाब देना चाहिए।

ई-पंजीकरण प्रणाली के विरोध में पूर्व अध्यक्ष राम आसरे शर्मा ने बेनामा लेखकों को दिया समर्थन



अनिल वशिष्ठ

मोदीनगर (वेलकम इंडिया)। तहसील मोदीनगर में ई-पंजीकरण प्रणाली के विरोध में चल रहे बेनामा लेखकों के धरने को मंगलवार को पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष राम आसरे शर्मा ने अपना समर्थन दिया। उन्होंने धरना स्थल पर पहुंचकर आंदोलनरत बेनामा लेखकों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुना। राम आसरे शर्मा ने कहा कि ई-पंजीकरण प्रणाली में आ रही तकनीकी खामियों के कारण आम जनता, किसानों, व्यापारियों तथा दस्तावेज लेखकों को अनावश्यक

पेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सरकार को इस व्यवस्था में व्याप्त कमियों को दूर करते हुए ऐसी प्रणाली लागू करनी चाहिए, जिससे पंजीकरण कार्य बिना बाधा के सुचारु रूप से संचालित हो सके। उन्होंने कहा कि बेनामा लेखकों की मांगों को ध्यान में रखा जाए और उनका शीघ्र समाधान किया जाना चाहिए। उन्होंने आंदोलनकारियों को हर संभव सहयोग का भरोसा देते हुए कहा कि जनहित के इस मुद्दे पर वह उनके साथ खड़े हैं। धरने पर मौजूद बेनामा लेखकों ने समर्थन के लिए राम आसरे शर्मा का आभार व्यक्त करते हुए सरकार से जल्द समाधान की मांग दोहराई।

मोदी आइफा आर्ट गैलरी में चल रही रंग तरंग कला प्रदर्शनी के समापन, कलाकारों को किया सम्मानित

अनिल वशिष्ठ

मोदीनगर (वेलकम इंडिया)। गैलाड बिल्डिंग स्थित मोदी आइफा आर्ट गैलरी में चल रही 'रंग तरंग' सात दिवसीय कला प्रदर्शनी के अंतिम दिन कलाकारों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि राजकुमार सागवान (सांसद बागपत क्षेत्र) एवं विशिष्ट अतिथि विनोद वैशाली (नगर पालिका अध्यक्ष मोदीनगर), भूतपूर्व राज्य मंत्री रामकिशोर अग्रवाल, भाजपा नेता पवन सिंघल एवं श्री उमेश मेहता (सीनियर आर्टिस्ट) भाजपा नेता स्वदेश जैन ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। मोदी आइफा आर्ट गैलरी में जिन कलाकारों ने अपनी स्व-निर्मित कलाकृतियों को प्रदर्शित किया था उन सभी कलाकारों को मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथियों द्वारा भागीदारी प्रमाण पत्र, गैलरी कैटलॉग एवं प्रतीक चिन्ह (ट्रॉफी) देकर सम्मानित किया।



कार्यक्रम के दौरान संस्थान के शिक्षक एवं अधिकारियों ने मुख्य अतिथि एवं अन्य विशिष्ट अतिथियों को गले में फटका पहनकर एवं ट्रॉफी देकर सम्मानित किया। उमेश मेहता की चित्रकृत आर्ट गैलरी द्वारा प्रकाशित 'अवींद्रनाथ गोमरे नाथ टैगोर' पुस्तक का विमोचन भी डॉ. राजकुमार सागवान कर कप्तन से किया गया। सांसद जी ने गैलरी के कैटलॉग का भी विमोचन किया इस समारोह में अमित महेश्वरी, आर.सी.शर्मा, मातृभूमि सेवा संघ के अध्यक्ष विकास भारती पवन चौधरी भी उपस्थित थे। संस्थान की ओर से प्रीति शर्मा ने सभी आगुतक

कलाकारों, कला प्रेमी, छात्र-छात्राओं और उनके माता-पिता, अभिभावक, शिक्षकों, एवं सामाजिक संस्थाओं से आए सभी को प्रदर्शनी में शिरकत करने का धन्यवाद दिया। सफल बनाने के लिए अमित कुमार बंसल का विशेष योगदान रहा जिन्होंने अधिकांश अतिथियों और अन्य मोदीनगर के सम्मानित व्यक्तियों को प्रदर्शनी को देखने के लिए आमंत्रित किया। अंत में इस प्रदर्शनी को सफल बनाने के लिए संस्थान डॉ. रुचि विद्यार्थी, प्रीति शर्मा, प्रशांत झा, शीतल रानी, अंजलि, स्वीटी, दीपांशु, पलक, आभा शर्मा, आदि का विशेष सहयोग रहा।

राम मंदिर दान चोरी के विरुद्ध कांग्रेस पार्टी का विरोध प्रदर्शन



अनिल वशिष्ठ

मोदीनगर (वेलकम इंडिया)। तहसील में शहर कांग्रेस कमेटी मोदीनगर के तत्वाधान में राम मंदिर चोरी के विरोध में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने शहर अध्यक्ष मोदीनगर बृजेश कुमार सेन और पीसीसी सदस्य उत्तर प्रदेश पंडित सुनील शर्मा के नेतृत्व में एसडीएम कार्यालय के सामने हनुमान चालीसा का पाठ कर राम मंदिर में दान चोरी के खिलाफ अपना विरोध प्रकट किया और सरकार और मंदिर के चोरी के खिलाफ नारेबाजी कर राम मंदिर परिसर में हुई दान चोरी में शामिल राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्य और उनके सहायकों के लिए फांसी

की सजा की मांग की। इस अवसर पर शहर अध्यक्ष बृजेश कुमार सेन, पीसीसी सदस्य सुनील शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने राम मंदिर ट्रस्ट का निर्माण किया था इसमें शामिल प्रत्येक ट्रस्ट के सदस्य के द्वारा किए गए कार्यों की जिम्मेदारी पूर्ण रूप से भारत के प्रधानमंत्री मोदी की बनती है उन्हें तुरंत नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। इस अवसर पर मुख्य रूप से ब्लॉक अध्यक्ष मोदीनगर चांद वीर चौधरी, महर्षि दयानंद मंडल अध्यक्ष राकेश सोनी, वीरेंद्र शर्मा, समसा खान, भिखारी लाल कश्यप, अनस सैफी, श्रीओम शर्मा और सुरेश दोसा के साथ अनेक कांग्रेसी कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

49वीं यूपी स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप में गाजियाबाद शूटिंग क्लब का शानदार प्रदर्शन, खिलाड़ियों ने जीते 44 पदक

वेलकम इंडिया संवाददाता

गाजियाबाद। डॉ. करणी सिंह शूटिंग रेंज, तुगलकाबाद में आयोजित 49वीं यूपी स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप में गाजियाबाद शूटिंग क्लब के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए क्लब का नाम रोशन किया। प्रतियोगिता में क्लब के खिलाड़ियों ने कुल 44 पदक जीतकर अपनी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया। इस प्रतियोगिता में गाजियाबाद शूटिंग क्लब के 55 खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया, जिसमें से 50 खिलाड़ियों ने नॉर्थ जोन चैंपियनशिप के लिए क्वालीफाई किया। पदक विजेता खिलाड़ी: रुद्र कर्दम - 3 स्वर्ण, 1 रजत, आहाना - 3 स्वर्ण, अर्जुन त्यागी - 2 स्वर्ण, विज्या चौधरी - 1 स्वर्ण, 1 कांस्य, भव्या यादव - 1 स्वर्ण, 2 कांस्य, अनन्या वाघवा - 1 स्वर्ण, 1 रजत, गायत्री - 2 स्वर्ण, 1 कांस्य, हर्षित कर्दम - 1 स्वर्ण, 1 रजत, राधिका - 1 स्वर्ण, नैना त्यागी - 1 स्वर्ण, 1 कांस्य, आर्णा, श्वेता चौधरी, श्वेता पाल, श्वेता शर्मा, अर्पिता, काव्या - 1-1 स्वर्ण, रिशभ त्यागी - 2 कांस्य, रितांशु



यादव - 1 कांस्य, कुशाग्र - 2 कांस्य, दिव्यांश तोमर - 2 कांस्य, गीतिका श्रीवास्तव - 1 कांस्य, राजत यादव - 1 कांस्य, देवांश - 1 कांस्य, अरविंद चौधरी - 1 कांस्य, यशवर्धन - 1 कांस्य, उद्ध अभिषेक यादव - 2 स्वर्ण पदक। क्लब के खिलाड़ियों की इस शानदार उपलब्धि पर कोच शिवम त्यागी ने सभी पदक विजेता खिलाड़ियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों की मेहनत, अनुशासन

और नियमित अभ्यास का परिणाम है कि गाजियाबाद शूटिंग क्लब लगातार सफलता के नए आयाम स्थापित कर रहा है। अजय प्रमुख ने सभी खिलाड़ियों के उज्वल भविष्य की कामना करते हुए आगामी प्रतियोगिताओं के लिए शुभकामनाएं दीं। गाजियाबाद शूटिंग क्लब निशानबाजी के क्षेत्र में नई प्रतिभाओं को तैयार करने और देश का नाम रोशन करने के लिए निरंतर प्रयासरत है।

दबंगों पर प्रशासन का बुलडोजर नहीं, कानून चला: वृद्ध की बेटी को वापस मिला अपना प्लाट



कपिल चौहान

लोनी। अवैध कब्जों के खिलाफ प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए एक वृद्ध व्यक्ति की शिकायत पर उसकी पुत्री के प्लाट को कब्जा मुक्त करा दिया। पुलिस और प्रशासन की संयुक्त कार्रवाई से पीड़ित परिवार को राहत मिली। वृद्ध माता प्रसाद ने उपजिलाधिकारी लोनी के समक्ष शिकायत दर्ज कराई थी कि डीएलएफ अंकुर विहार के प्रेम विहार स्थित उनकी पुत्री के प्लाट पर कुछ दबंगों ने अवैध कब्जा कर लिया है। आरोप था कि वे उन्हें प्लाट पर जाने से रोक रहे हैं और धमकियां

भी दे रहे हैं। शिकायत पर तत्काल संज्ञान लेते हुए प्रशासन ने मामले की जांच कराई। जांच में आरोप सही पाए जाने के बाद ज्वाइंट मजिस्ट्रेट एवं उपजिलाधिकारी लोनी दीपक सिंहनवाल के निर्देशन में पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचकर प्लाट को कब्जा मुक्त कराया गया और शिकायतकर्ता को उसका वैध कब्जा दिलाया गया। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट एवं उपजिलाधिकारी दीपक सिंहनवाल ने कहा कि तहसील लोनी क्षेत्र में किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि भविष्य में भी अवैध कब्जाधारियों के विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी।

खेत बचाओ अभियान के अंतर्गत ब्लॉक भोजपुर में किसान जागरूकता कार्यक्रम का सफल आयोजन

अनिल वशिष्ठ

मोदीनगर (वेलकम इंडिया)। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) के निर्देशानुसार भाऊअनुप-केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, क्षेत्रीय केंद्र, मोदीपुरम, मेरठ द्वारा 'खेत बचाओ अभियान' के अंतर्गत आज ब्लॉक भोजपुर, स्थित ब्लॉक भवन में किसान जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में क्षेत्र के लगभग 87 किसानों एवं ग्रामीणों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि डॉ. (श्रीमती) मंजू सिवाच, विधायिका रहीं। उन्होंने कृषि की प्राचीन पद्धतियों एवं फसल विविधकरण को अपनाने पर जोर दिया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य किसानों को मृदा स्वास्थ्य संरक्षण, संतुलित उर्वरक उपयोग तथा टिकाऊ कृषि पद्धतियों के प्रति जागरूक करना था। इस अवसर पर संस्थान के वैज्ञानिक एवं अधिकारियों ने किसानों



को वैज्ञानिक खेती अपनाने तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के महत्व के बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान की। कार्यक्रम की अध्यक्षता श्रीमती सुचेता सिंह, ब्लॉक प्रमुख भोजपुर एवं कार्यक्रम सफल हो प्रभावी संचालन आशीष चौधरी, सदस्य, विकास खंड, भोजपुर द्वारा किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डॉ. बबिता चौधरी, प्रधान वैज्ञानिक ने मृदा परीक्षण, मृदा स्वास्थ्य

कार्ड तथा संतुलित पोषण प्रबंधन के महत्व पर विस्तृत प्रकाश डाला। इस अवसर पर डॉ. (श्रीमती) विनीत शर्मा, मुख्य तकनीकी अधिकारी ने 'खेत बचाओ अभियान' की रूपरेखा एवं उद्देश्यों की जानकारी देते हुए किसानों से मृदा संरक्षण, संतुलित उर्वरक उपयोग तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण को अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि स्वस्थ मिट्टी ही टिकाऊ एवं लाभकारी कृषि

की आधारशिला है। कार्यक्रम के दौरान किसानों ने वैज्ञानिकों के साथ मृदा स्वास्थ्य, उर्वरक प्रबंधन एवं आधुनिक कृषि तकनीकों से संबंधित विभिन्न विषयों पर चर्चा की तथा अपनी जिज्ञासाओं का समाधान प्राप्त किया। अभियान के अंतर्गत 50 किसानों को डैंचा बीज एवं माइक्रोबियल कंसोर्टिया भी वितरित किए गए, जिससे हरित खाद एवं मृदा स्वास्थ्य सुधार को बढ़ावा मिल सके।

एंजल मॉल में हुक्का बार पर पुलिस का बड़ा एक्शन, दो क्लबों में छापा; 10 गिरफ्तार



कपिल चौहान

गाजियाबाद (वेलकम इंडिया)। कोशाम्बी थाना पुलिस ने एंजल मॉल स्थित द पब्लिक हाउस और द ब्लू क्लब में चल रहे अवैध हुक्का बारों पर मंगलवार को छापीकारी कर 10 लोगों को गिरफ्तार किया। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने मौके से 9 हुक्के, 9 चिलम, 9 पाइप और 4 फ्लेवरयुक्त तंबाकू के डिब्बे बरामद किए। पुलिस के अनुसार, मुखबिर से सूचना मिली थी कि दोनों क्लबों में अवैध रूप से श्राहकों को हुक्का और फ्लेवरयुक्त तंबाकू उपलब्ध कराया जा रहा है। सूचना के सत्यापन के

बाद पुलिस टीम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए दोनों क्लबों में छापा मारा और पांच-पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से हुक्का और तंबाकू उत्पाद बरामद किए गए। सभी के विरुद्ध सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम (COTPA), 2003 की धारा 21/22 के तहत मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्रवाई शुरू कर दी गई है। पुलिस का कहना है कि जनस्वास्थ्य और कानून व्यवस्था को प्रभावित करने वाले अवैध हुक्का बारों के खिलाफ अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा।

पुरानी पेंशन योजना को आगामी संसद सत्र में बहाल किया जाए: मो0 अरशद खान

वेलकम इंडिया ब्यूरो

जौनपुर। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव एवं जौनपुर सदर के पूर्व विधायक मोहम्मद अरशद खान ने केंद्र सरकार से मांग की है कि आगामी संसद सत्र में पुरानी पेंशन योजना (डडर) को पूरे देश के सरकारी कर्मचारियों के लिए पुनः लागू करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया जाए। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की वर्षों की सेवा, उनके सम्मान, सामाजिक सुरक्षा तथा बुढ़ापे के सुरक्षित जीवन को ध्यान में रखते हुए अब पुरानी पेंशन योजना की बहाली समय की सबसे बड़ी आवश्यकता बन चुकी है। मोहम्मद अरशद खान ने कहा कि 'वन नेशन, वन पेंशन' की भावना के अनुरूप देश

के सभी सरकारी कर्मचारियों को समान रूप से पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि एक कर्मचारी अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण वर्ष देश और समाज की सेवा में समर्पित करता है, इसलिए सेवानिवृत्ति के बाद उसके सम्मानजनक जीवन की जिम्मेदारी भी सरकार की होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि वर्ष 2004 में तत्कालीन केंद्र सरकार द्वारा पुरानी पेंशन व्यवस्था को समाप्त कर नई पेंशन योजना (NPS) लागू किया जाना एक ऐसा निर्णय था, जिसका समीक्षा अब आवश्यक हो गई है। उन्होंने कहा कि यह व्यवस्था कर्मचारियों की पेंशन को शेर बाजार के उतार-चढ़ाव से जोड़ देती है, जिससे सेवानिवृत्ति के बाद



मिलने वाली राशि निश्चित नहीं रहती। ऐसे में कर्मचारी और उनका परिवार भविष्य को लेकर असुरक्षित महसूस करता है। इसलिए सरकार को इस व्यवस्था को समाप्त कर पुरानी, सुनिश्चित और गारंटीकृत पेंशन व्यवस्था को पुनः लागू करना चाहिए। मोहम्मद अरशद

खान ने कहा कि पुरानी पेंशन केवल आर्थिक सहायता नहीं, बल्कि कर्मचारियों के आत्मसम्मान, सामाजिक सुरक्षा और बुढ़ापे में आत्मनिर्भर जीवन का आधार है। एक कल्याणकारी राज्य का दायित्व है कि वह अपने कर्मचारियों को सेवा समाप्ति के बाद सम्मानजनक और सुरक्षित जीवन की गारंटी प्रदान करे। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी हमेशा कर्मचारियों, शिक्षकों, अधिकारियों और श्रमिक वर्ग के हितों में सहयोग करे। उन्होंने केंद्र सरकार से पुनः आग्रह किया कि आगामी संसद सत्र में पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने का विधेयक लाकर देश के लाखों कर्मचारियों और उनके परिवारों की वर्षों पुरानी मांग को पूरा किया जाए।

सरकार बनेगी और श्री अखिलेश यादव के नेतृत्व में पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की दिशा में प्रभावी कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने प्रदेश के सभी कर्मचारियों, शिक्षकों, पेंशन बहाली आंदोलन से जुड़े संगठनों तथा उनके परिवारों से आह्वान किया कि वे अपने अधिकारों की रक्षा और पुरानी पेंशन योजना को बहाली के लिए लोकतांत्रिक तरीके से संघर्ष जारी रखें तथा उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने में सहयोग करें। उन्होंने केंद्र सरकार से पुनः आग्रह किया कि आगामी संसद सत्र में पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने का विधेयक लाकर देश के लाखों कर्मचारियों और उनके परिवारों की वर्षों पुरानी मांग को पूरा किया जाए।

'ऑपरेशन प्रहार' का बड़ा वार: गाजियाबाद में 1.42 करोड़ के नशीले पदार्थ बरामद, ड्रग तस्कर दबोचा

कपिल चौहान

गाजियाबाद (वेलकम इंडिया)। नशे के कारोबार के खिलाफ चलाए जा रहे 'ऑपरेशन प्रहार' के तहत गाजियाबाद पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। थाना नंदग्राम पुलिस और एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (एएनटीएफ) मेरठ की संयुक्त टीम ने एक ड्रग तस्कर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे और निशानदेही पर करीब 1 करोड़ 42 लाख रुपये मूल्य के मादक पदार्थ, 5 लाख रुपये की ड्रग मनी, तस्करी में प्रयुक्त कार तथा अन्य उपकरण बरामद किए हैं। मुखबिर की सूचना पर आशियाना चौक पर संयुक्त चेकिंग के दौरान आरोपी को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ के बाद उसकी



निशानदेही पर इंद्रापुरम के शक्ति खंड स्थित एक फ्लैट में छापीकारी की गई, जहां से भारी मात्रा में अवैध मादक पदार्थ, तस्करी में इस्तेमाल होने वाले उपकरण, घंटाना में प्रयुक्त कार और 5 लाख रुपये नकद बरामद हुए। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि बरामद सामान की कुल अनुमानित कीमत लगभग 1.42

करोड़ रुपये है। आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। साथ ही पुलिस उसके नेटवर्क, सप्लायर्स और इस अवैध कारोबार से जुड़े अन्य लोगों की तलाश में जुटी है। कमिश्नरेंट पुलिस का कहना है कि जिले में नशे के कारोबार के खिलाफ अभियान आगे भी इसी तरह सख्ती से जारी रहेगा।

श्री राधा माधव लीला महोत्सव में श्यामानंद प्रभु के चरित्र और राधा-कृष्ण विवाह प्रसंग का भावपूर्ण वर्णन

वेलकम इंडिया संवाददाता

मुरादनगर। मित्र मंडल धार्मिक सेवा समिति के तत्वावधान में राणा फार्म हाउस, अग्रसेन मार्केट, मुरादनगर में आयोजित श्री राधा माधव लीला महोत्सव में वृंदावन से पधारे राष्ट्रीय संत परम श्रद्धेय श्री गौर दास जी महाराज ने श्रद्धालुओं को श्यामानंद प्रभु के जीवन चरित्र एवं राधा-कृष्ण विवाह प्रसंग का भावपूर्ण वर्णन सुनाया।

कथा के दौरान श्री गौर दास जी महाराज ने बताया कि श्यामानंद प्रभु का प्रारंभिक नाम कृष्ण दास था। बंगाल में अपने गुरु की आज्ञा से उन्होंने टाकुरजी की वाटिका में जल सिंचन की सेवा अत्यंत निष्ठा और समर्पण के साथ की। उनकी सेवा-भावना से प्रसन्न होकर गुरु ने उन्हें वृंदावन जाकर श्री जीव गोस्वामी जी के सान्निध्य में भजन एवं सेवा करने का निर्देश दिया।

उन्होंने बताया कि श्री जीव गोस्वामी जी ने कृष्ण दास को सेवकृज में प्रतिदिन बुहारी (सोहनी सेवा) करने की आज्ञा दी और समझाया कि वृंदावन धाम में सेवा और वैष्णवों के प्रति सम्मान ही भक्ति का आधार है। इसी सेवा के दौरान एक दिन उन्हें श्री राधाधारी का नूपुर प्राप्त हुआ। इसके बाद उन पर श्री राधा-कृष्ण की विशेष



कृपा हुई और उन्हें श्यामसुंदर स्वरूप की सेवा का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसी घटना के बाद उनका नाम श्यामानंद प्रभु के रूप में प्रसिद्ध हुआ।

कथा के दूसरे प्रसंग में महाराज श्री ने राधा-कृष्ण विवाह महोत्सव का अत्यंत मनोहारी वर्णन किया। उन्होंने बताया कि मथुरा के एक राजा को स्वप्न में श्री राधाधारी ने आदेश दिया कि उनका विवाह वृंदावन में विराजमान श्यामसुंदर से कराया जाए। कार्यक्रम के यजमान अरविंद गर्ग, संजय कंसल तथा उद्योग व्यापार मंडल के जिला महामंत्री पंकज गर्ग ने सभी



श्रद्धालुओं एवं अतिथियों का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम के समापन पर सुनील सिंघल, संजय सिंघल, कुलदीप गर्ग एवं संजय गुप्ता ने श्री गौर दास जी महाराज तथा उनके सहयोगियों को स्मृति-चिह्न भेंट कर सम्मानित किया।

कार्यक्रम के समापन पर सुनील सिंघल, संजय सिंघल, कुलदीप गर्ग एवं संजय गुप्ता ने श्री गौर दास जी महाराज तथा उनके सहयोगियों को स्मृति-चिह्न भेंट कर सम्मानित किया।

आरटीई के तहत प्रत्येक चयनित बच्चे का दाखिला सुनिश्चित करे सरकार: सीमा त्यागी

प्रवेश से इनकार करने वाले निजी विद्यालयों की मान्यता रद्द करने की मांग



शैक्षणिक वर्ष	आरटीई सीटें	प्लेस
2022-23	5,067	3,206
2023-24	5,841	3,810
2024-25	6,065	3,158
2025-26	6,000	3,200
2026-27*	6,257	4,100
कुल	29,230	16,974

वेलकम इंडिया संवाददाता

गाजियाबाद। इंडियन पेरेंट्स एसोसिएशन की राष्ट्रीय अध्यक्ष सीमा त्यागी ने शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर चिंता जताते हुए सरकार से प्रत्येक चयनित बच्चे का निजी विद्यालयों में समयबद्ध प्रवेश सुनिश्चित कराने की मांग की है। उन्होंने कहा कि आरटीई के तहत चयनित बच्चों को प्रवेश न देना कानून की मूल भावना और बच्चों के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है।

सीमा त्यागी ने कहा कि पिछले पांच वर्षों (शैक्षिक सत्र 2022-23 से 2026-27) के आंकड़े गंभीर स्थिति की ओर संकेत करते हैं। इस अवधि में आरटीई के अंतर्गत लगभग 29,230 बच्चों को निजी विद्यालयों

में सीटें आवंटित की गईं, लेकिन केवल 16,974 बच्चों को ही प्रवेश मिल सका। परिणामस्वरूप हजारों चयनित बच्चे आज भी अपने शिक्षा के अधिकार से वंचित हैं।

उन्होंने कहा कि जब सरकार और शिक्षा विभाग द्वारा चयनित बच्चों को भी निजी विद्यालय प्रवेश देने से इनकार कर रहे हैं, तो यह प्रशासनिक व्यवस्था और कानून के पालन पर गंभीर सवाल खड़े करता है। उन्होंने प्रदेश सरकार, जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग से मांग की कि प्रत्येक चयनित बच्चे का शीघ्र प्रवेश सुनिश्चित किया जाए तथा अभिभावकों को शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण किया जाए।

सीमा त्यागी ने यह भी मांग की कि आरटीई के तहत प्रवेश देने से इनकार करने वाले अध्यापक शासन एवं

शिक्षा विभाग के निर्देशों की अवहेलना करने वाले निजी विद्यालयों के विरुद्ध शिक्षा का अधिकार अधिनियम, उत्तर प्रदेश आरटीई नियमावली तथा अन्य प्रासंगिक कानूनी प्रावधानों के तहत कड़ी कार्रवाई की जाए। आवश्यकता पड़ने पर ऐसे विद्यालयों की मान्यता निरस्त करने की प्रक्रिया भी शुरू की जानी चाहिए।

उन्होंने कहा कि आरटीई का उद्देश्य केवल चयन सूची जारी करना नहीं, बल्कि प्रत्येक चयनित बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है।

जब तक हर पात्र बच्चे का विद्यालय में प्रवेश सुनिश्चित नहीं होगा, तब तक शिक्षा का अधिकार अधूरा रहेगा। सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कोई भी चयनित बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे।

सड़क पर मामूली टक्कर बनी मौत की वजह, लोनी बॉर्डर में युवक की पीट-पीटकर हत्या



कपिल चौहान

गाजियाबाद (वेलकम इंडिया)। लोनी बॉर्डर थाना क्षेत्र में कार और बाइक की मामूली टक्कर के बाद हुआ विवाद एक युवक की मौत का कारण बन गया। मुस्तफाबाद निवासी जैद की कथित तौर पर कार सवार युवकों ने बेरहमी से पिटाई कर दी, जिससे उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई।

जानकारी के अनुसार, जैद बाइक से जा रहा था। इसी दौरान उसकी बाइक की एक कार से हल्की टक्कर हो गई। टक्कर के बाद दोनों पक्षों के बीच कहासुनी शुरू हुई, जो देखते ही देखते मारपीट में बदल गई। आरोप है कि कार सवार युवकों ने



जैद पर हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। घायल जैद को तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों में शोक और आक्रोश का माहौल है। पुलिस के अनुसार, परिजनों की तहरीर के आधार पर हत्या सहित संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कई पुलिस टीमें गठित की गई हैं। पुलिस सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुटी है। अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जाएगी।

पुलिस की कार्यप्रणाली में संवेदनशीलता और त्वरित न्याय की मांग, मुख्यमंत्री के नाम सौपा ज्ञापन

सुमित सोरेन

गाजियाबाद (वेलकम इंडिया)। 'सजग समाज अभियान गाजियाबाद' के तत्वावधान में विभिन्न सामाजिक एवं धार्मिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट पहुंचकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में गाजियाबाद पुलिस की कार्यप्रणाली को अधिक संवेदनशील, पारदर्शी और जवाबदेह बनाने तथा लंबित मामलों में समयबद्ध न्याय सुनिश्चित करने की मांग की गई।

ज्ञापन में कहा गया कि जिले में अनेक पीड़ित, विशेषकर महिलाएं, अपनी शिकायतों पर त्वरित एवं प्रभावी कार्रवाई के लिए लंबे समय तक इंतजार करने को विवश हैं। कई मामलों में प्राथमिकी दर्ज करने में विलंब, जांच की धीमी गति तथा पीड़ितों के प्रति अपेक्षित संवेदनशीलता के अभाव जैसी समस्याएं सामने आ रही हैं, जिससे आमजन का न्याय व्यवस्था पर विश्वास प्रभावित हो रहा है। प्रतिनिधिमंडल ने मांग की कि सभी लंबित मामलों की उच्चस्तरीय समीक्षा कर निश्चित समय-सीमा में जांच पूरी कराई जाए तथा दोषियों के विरुद्ध



कानून के अनुसार कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। इसके अलावा पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए नियमित रूप से संवेदनशीलता और मानवाधिकार संबंधी प्रशिक्षण आयोजित किए जाएं, प्रत्येक थाने में पीड़ित सहायता एवं शिकायत निगरानी डेस्क स्थापित की जाए तथा कर्तव्य में

लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय जांच कर जवाबदेही तय की जाए। ज्ञापन में लोनी के अंकुर विहार थाना क्षेत्र में दर्ज धर्मांतरण प्रकरण (एफआईआर संख्या 113/2026) का उल्लेख करते हुए कहा गया कि ऐसे संवेदनशील मामलों में निष्पक्ष, पारदर्शी और समयबद्ध

कार्रवाई सुनिश्चित की जानी चाहिए। प्रतिनिधियों ने विश्वास जताया कि प्रदेश सरकार कानून व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाए, पीड़ितों को समय पर न्याय दिलाए तथा पुलिस व्यवस्था में जनता का विश्वास मजबूत करने के लिए आवश्यक कदम उठाएगी। ज्ञापन सौंपने वालों में सजग समाज अभियान गाजियाबाद, हिन्दू रक्षा मंच, अपराध मुक्त गाजियाबाद सेवा समिति, जाटव सभा, सर्व सेवा परिषद, भारतीय किसान यूनियन (अनाज), अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा, किसान यूनियन इंडिया, शिव शक्ति सेवा ट्रस्ट, राष्ट्रवादी श्रवण महासंघ एवं विश्व हिन्दू रक्षा परिषद सहित विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि शामिल रहे। इस अवसर पर राकेश चौहान, नवनीत सिंह, मुकेश शर्मा, रणवीर सिंह, संतोष राणा, सुमित अरोड़ा, अरुण कुमार, एडवोकेट चंद्रपाल सिंह, शुभांजलि त्रिपाठी, अरुण बैसला, अरविंद गुप्ता, वारिज सिंह, डॉ. सतीश गुप्ता, ओम तिवारी, राहुल चौधरी, आकाश वर्मा, ललित कश्यप, राजीव चौहान, पंकज कंसल, सुबोध जाटव, पूनम कांत, सपना कंसल, सुरेश कुशवाहा सहित अनेक सामाजिक कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

हर समय, हर जगह सुरक्षा का मरोसा: लखनावली में शुरू हुआ नया पुलिस बूथ



कपिल चौहान

ग्रोटर नोएडा। क्षेत्र में कानून-व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करने तथा पुलिस सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से थाना सुरजपुर क्षेत्र के लखनावली में नए पुलिस बूथ का लोकार्पण किया गया। इस पहल से स्थानीय लोगों को आपात स्थिति में तत्काल पुलिस सहायता उपलब्ध हो

सकेगी। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि नए पुलिस बूथ के संचालन से क्षेत्र में पुलिस की सतत निगरानी बढ़ेगी, अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाने में मदद मिलेगी तथा नागरिकों में सुरक्षा का भाव और मजबूत होगा। पुलिस से कहा कि जनसहयोग के साथ सुरक्षित और अपराधमुक्त वातावरण बनाए रखने के लिए वह निरंतर कार्य कर रही है। स्थानीय लोगों ने भी इस पहल का स्वागत करते हुए इसे क्षेत्र की सुरक्षा

गाजियाबाद की ट्रैफिक व्यवस्था संभालने की तैयारी, 200 प्रशिक्षु आरक्षियों को एडीसीपी ने पढ़ाया जिम्मेदारी का पाठ

कपिल चौहान

गाजियाबाद (वेलकम इंडिया)। कमिश्नरेट गाजियाबाद की यातायात व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से मंगलवार को 47वीं बटालियन पीएसी में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे 200 प्रशिक्षु आरक्षियों को अपर पुलिस उपायुक्त (यातायात) वरुण कुमार सिंह ने संबोधित किया। उन्होंने यातायात पुलिस की कार्यप्रणाली, नियमों, अनुशासन और ड्यूटी के दौरान निभाई जाने वाली जिम्मेदारियों की विस्तार से जानकारी दी। एडीसीपी ने कमिश्नरेट क्षेत्र में बढ़ते यातायात दबाव और सड़क सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियों का उल्लेख करते हुए प्रशिक्षु



आरक्षियों को प्रभावी ट्रैफिक प्रबंधन के व्यावहारिक पहलुओं से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि यातायात पुलिस की भूमिका केवल नियमों का पालन करना नहीं, बल्कि आमजन को सुरक्षित और सुगम यातायात उपलब्ध कराना भी है। संवाद के दौरान उन्होंने आरक्षियों को निष्पक्ष, अनुशासित और संवेदनशील तरीके से ड्यूटी निभाने के लिए प्रेरित किया। साथ ही सड़क सुरक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करने और दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए पूरी निष्ठा के साथ कार्य करने का आह्वान किया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में सभी प्रशिक्षु आरक्षियों ने यातायात व्यवस्था से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों की जानकारी प्राप्त की।

खोड़ा में ट्रांसफार्मर से उठी लपटें बनीं आग का तांडव, ऑयल के ड्रमों ने बढ़ाई तबाही; 4 मकान और कई दुकानें जलीं

कपिल चौहान

गाजियाबाद (वेलकम इंडिया)। खोड़ा थाना क्षेत्र की आदर्श नगर कॉलोनी में ट्रांसफार्मर में हुए शॉर्ट सर्किट के बाद भीषण आग लग गई। ट्रांसफार्मर के पास खाली प्लॉट में रखे 25 से 30 ड्रम ऑयल ने आग को और बढ़ा दिया, जिससे कुछ ही देर में आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। आग की चपेट में तीन से चार मकान और कई दुकानें आ गईं।

आग लगते ही पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई। लोग जान बचाने के लिए घरों से बाहर निकल आए। इस दौरान एक महिला ने अपनी जान बचाने के लिए घर की बालकनी से छलांग लगा दी, जिससे वह घायल



हो गई। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीमें मौके पर पहुंचीं, लेकिन संकरी गलियों के कारण फायर ब्रिगेड की गाड़ियां घटनास्थल तक नहीं पहुंच सकीं। इसके बाद करीब 500 मीटर तक पाइप बिछाकर कड़ी मशकत के बाद आग पर काबू पाया गया।



घटना में कोई जनहानि नहीं हुई, हालांकि कुछ लोग मामूली रूप से घायल हुए, जिन्हें स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। समय रहते आग पर काबू पा लेने से बड़ा हादसा टल गया। आग बुझने के बाद स्थानीय लोगों ने तालियां

बजाकर दमकल कर्मियों का आभार जताया।

फिलहाल पुलिस और दमकल विभाग आग लगने के कारणों की जांच कर आगे की कार्रवाई में जुटे हैं।

डिजिटल सहकारिता से किसानों को मिलेगा लाभ, संतुलित उर्वरक उपयोग पर हुआ मंथन

कपिल चौहान

गाजियाबाद (वेलकम इंडिया)। विकास भवन सभागार में सहकारिता क्षेत्र में डिजिटल बदलाव, संतुलित उर्वरक उपयोग और सहकारी संस्थाओं को मजबूत बनाने के उद्देश्य से सामूहिक परिचर्चा कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की

अध्यक्षता जिला कृषि अधिकारी अमित कुमार सिंह ने की। जिला कृषि अधिकारी ने उर्वरकों के संतुलित एवं वैज्ञानिक उपयोग, उर्वरक लाइसेंस प्रक्रिया तथा कृषि में आधुनिक तकनीकों के महत्व पर विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि डिजिटल तकनीक अपनाने से सहकारी



संस्थाओं को कार्यप्रणाली अधिक पारदर्शी, प्रभावी और किसान हितैषी बनेगी। अपर जिला सहकारी अधिकारी जे.पी.एस. गौतम ने सहकारी समितियों की भूमिका और किसानों को मिलने वाले लाभों पर प्रकाश डाला। वहीं कृषकों के उप प्रबंधक सत्यवीर सिंह ने किसान हितैषी

योजनाओं, डिजिटल पहल और संतुलित उर्वरक उपयोग के महत्व को बताते हुए कहा कि टिकाऊ कृषि और किसानों की आय बढ़ाने के लिए संतुलित पोषण आवश्यक है। कार्यक्रम में उप जिला कृषि अधिकारी शताक्षी मिश्रा सहित सहकारिता एवं कृषि विभाग के अधिकारियों ने भी अपने विचार रखे

और विभागों के समन्वित प्रयासों पर बल दिया। कार्यक्रम में सहकारिता विभाग और जिला कृषि अधिकारी कार्यालय के लगभग 30 अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने भाग लिया। अंत में कृषकों के उप प्रबंधक सत्यवीर सिंह ने अतिथियों को पुष्पगुच्छ भेंट कर सम्मानित किया तथा सभी प्रतिभागियों का आभार व्यक्त किया।